Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding construction of canals through Ken-Betwa River Linking Project to overcome the problem of water scarcity and stray cows in the Bundelkhand.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 17, प्राइवेट संकल्प । बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की समस्या को दूर करने के लिए केन-बेतवा नदी संपर्क परियोजना द्वारा नहरों का निर्माण । मैंने आज व्यवस्था दे दी है कि माननीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे ।

श्री हनुमान बेनीवाल । आपका बुंदेलखंड से क्या संबंध है?

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): अध्यक्ष जी, मैं इनका साथ दे रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी द्वारा पेश कि ए गए संकल्प- बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की समस्या को दूर करने के लिए केन-बेतवा नदी संपर्क परियोजना द्वारा नहरों का निर्माण, की चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता हमारे पुष्पेन्द्र सिंह जी ने की है । बुंदेलखंड इलाके, छुट्टा गोवंश और पीने के पानी सहित सिंचाई के पानी की कैसे ठोस व्यवस्था हो, इसके लिए चिंतित नजर आए ।

अध्यक्ष महोदय, यह बुंदेलखंड की नहीं, पूरे देश की समस्या है । वर्ष 2016 में नीति आयोग व यूएनडीपी के सौजन्य से प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में यह कहा गया था कि अन्ना प्रथा, उस प्रथा को संदर्भित करता है, जहां जानवर रबी की फसल की कटाई के बाद घूमने के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं । इस प्रकार की परम्परा के पीछे इतिहास यह है कि बहुत समय पहले चारा और पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता था तो कि सान लीन सीजन में अपने मवेशियों को चराने के लिए छोड़ देते थे । लेकिन आज के इस जल संकट के दौर में स्थितियां बदल गयी हैं, हर साल इस तरह से घूमने वाले मवेशी न केवल फसल का एक

बड़ा हिस्सा नष्ट कर देते हैं, बल्कि सड़कों पर एक्सीडेंट्स का बहुत बड़ा कारण भी बनते हैं । नीलगाय सड़क पर चलते हुए आ जाती है । हम अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं, टेलिविजन और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि नीलगाय गाड़ी पर गिरी, मौतें हो गयीं, मोटरसाइकिल से टकराई, मौत हो गयी । इससे जान-माल की बहुत हानि होती है, यह समस्या केवल बुंदेलखंड तक ही सीमित नहीं है, यह समस्या हर उस कृषि प्रधान क्षेत्र की समस्या है, जो कि पानी की कमी और मवेशियों के आंतक से परेशान है ।

मैं आप सभी का आभारी हूं कि आज यह सदन इन समस्याओं के कारणों के निदान के लिए बात करने के लिए एकत्रित हुआ है । अध्यक्ष जी, उस दिन भी जब मैं प्राइवेट मैम्बर्स बिल पर अंतिम वक्ता के रूप में बोल रहा था तो मुझ से पहले भी कई विद्वान वक्ताओं ने अपनी राय रखी थी । अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान से आता हूं, जहां राज्य की तकरीबन 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, तथा अपने जीवनयापन के लिए कृषि और कृषि से संबंधित एक्टिविटीज़ में लगी हुई है । राजस्थान में कृषि तकरीबन 14 मिलियन कि सानों और 5 मिलियन काश्तकारों के लिए रोजगार का साधन है । यही वजह है कि आज के प्रस्ताव के दोनों प्रमुख मुद्दे -आवारा पशु और सिंचाई, मेरे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं ।

अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र में पहले ही अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, गिरता भू-जल स्तर, लम्बे समय तक पड़ने वाला अकाल जैसी अनेक समस्याएं हैं । इनके अलावा मवेशियों को त्यागने से कृषि समस्याएं और ज्यादा विकराल हो रही हैं । गांवों और नगरों में मवेशियों का आतंक बढ़ा हुआ है और यह इस हद तक बढ़ गया है कि राज्यों को उन्हें रहने की जगह मुहैया कराने के लिए कर लगाना पड़ रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, कई किसानों ने आवारा पशुओं से अपनी फसलों को बचाने के लिए बाड़-बंदी का इंतजाम कि या । लेकिन बाड़-बंदी से खेती की लागत बढ़ गयी । पौने चार हेक्टेयर खेत की बाड़-बंदी का खर्च 8 से 10 हजार रुपये बैठता है । इसमें मरम्मत की लागत भी जुड़ती है । मवेशी बार-बार बाड़-

बंदी को नुकसान पहुंचाते हैं । बहुत से किसान परिवार ऐसे हैं, जो यह खर्च झेलने की स्थिति में नहीं हैं । जो लोग अपने खेतों में बाड़-बंदी कराने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार को खुद व्यवस्था करनी चाहिए, राज्य सरकारों को व्यवस्था करनी चाहिए । दिल्ली की सरकार को इस मामले में सुध लेनी चाहिए ।

जो लोग अपने खेतों में बाड़बंदी कराने में असमर्थ हैं, जो 24 घंटे अपने खेतों की रखवाली खुद करते हैं, लेकिन रखवाली में थोड़ी-सी चूक होने पर मवेशी फसलों को नष्ट कर देते हैं । ऐसे में खेती में आमदनी की उम्मीद खो चुका किसान अपने परिवार के जीवनयापन के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए विवश है । गांव खाली हो रहे हैं, रोजगार के साधन नहीं हैं । जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहां लोग वर्षा की खेती पर निर्भर करते हैं । रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं मिलने से गांव के गांव खाली हो रहे हैं और शहरों की आबादी बढ़ रही है । हमें इस देश के किसान को बचाना है ।

महोदय, मेरी इस सदन के माध्यम से यह गुजारिश है कि खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर चारागाह या मवेशी अभियान बनाए जाएं, ताकि कृषि में उपजे मानव-मवेशी संघर्ष को समाप्त किया जा सके । महोदय, योजनाबद्ध विकास के बाद भी आज़ादी मिले हुए 70 सालों से भी अधिक का समय व्यतीत हो गया है । मगर राजस्थान आधारभूत संरचना की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहां कृषि योग्य भूमि का दो तिहाई भाग वर्षा पर निर्भर करता है । पानी के इस्तेमाल में कोई भी सावधानी नहीं बरती जा रही है, जिससे जल संसाधनों की निरंतरता पर संदेह बन चुका है । इसका मतलब यह है कि सरकार की पीने के पानी की आपूर्ति से जुड़ी हुई योजनाओं में ही कई तरह की समस्याएं हैं । यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हम अभी हर खेत को पानी पहुंचाने के लक्ष्य से बहुत दूर हैं ।

महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं, हमारे जल शक्ति मंत्री जी जोधपुर जिले से आते हैं । बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर में ऐसे इलाके हैं, जो देश सेवा के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक देते हैं । लेकिन अभी हम लोग पीने के पानी से भी बहुत दूर हैं । जब से माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने सत्ता संभाली है, तब से यह

उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, अटल जी ने नदी से नदी को जोड़कर हर खेत के लिए सिंचाई के पानी की एक उम्मीद जगाई थी । हर व्यक्ति यह चाहता है कि नरेन्द्र मोदी जी हर खेत को सिंचाई का पानी देंगे और किसानों को बचाएंगे ।

16.07 hrs (Shrimati Meenakashi *in the Chair*)

महोदया, मैं मंत्री जी का भी ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि अभी हम इस लक्ष्य से काफी दूर हैं । हर खेत को सिंचाई का पानी कैसे मिले, आप उस धरती से आते हैं, जहां हमेशा हमारे किसानों ने अकाल का सामना किया है । नागौर, जोधपुर और बाड़मेर के अंदर बहुत ही अलग परिस्थितियों से वहां का कि सान संघर्ष करता रहा है । वहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है । वहां बड़ी तकलीफ के दौर से किसान गुजरे हैं । पानी की आपूर्ति की निरंतरता को बनाए रखने हेतु पूर्व प्रधान मंत्री जी की महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना, जल संसाधन प्रबंधन के असंतुलन को दूर करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम था, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जब वर्ष 2004 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, तो अटल जी जो योजना लाए थे, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी इस योजना के भारी भरकम खर्च को देखते हुए इस योजना से मुंह मोड़ लिया था । उन्होंने उसको डंप कर दिया है और कांग्रेस की उस सरकार ने देश के कि सानों को एक बार फिर प्यासा छोड़ दिया था ।

महोदया, राजस्थान के 10 जिलों की प्यास इंदिरा गांधी व भाखड़ा नहरें बुझाती हैं, जिनको पौंग व भाखड़ा बांधों से पानी मिलता है । इन बांधों में सतलुज और व्यास नदी का पानी आता है । मगर गत वर्ष इन बांधों के जल स्तर में काफी गिरावट आ गई थी । इन नदियों में पानी की घटी हुई मात्रा से कई जिले मुसीबत में फंस गए हैं । इन मुश्किलों को बढ़ाने में एक और कारण पिछले कुछ वर्षों से उभरकर आया है, जो कि प्रतिस्पर्धी संघवाद है, जिसमें कई राज्य दूसरे राज्यों को पानी देने से नकार रहे हैं । आपस में स्टेट, स्टेट से झगड़ा कर रहे हैं । इस संबंध में, मेरी सरकार से यह गुज़ारिश है कि देश के नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अंतर्देशीय जल ट्रांसफर परियोजना पर जल्दी से जल्दी प्रगति की जाए । हालांकि संविधान में पानी को राज्यों का

विषय माना गया है, लेकिन आज प्रतिस्पर्धी संघवाद की जगह सहकारी संघवाद का समय आ गया है । इसलिए, हम सभी को देश और देश का पेट भरने वाले कि सानों के हितों में नदी जोड़ो योजनाओं को जल्दी से जल्दी से क्रियान्वित कर हर खेत को पानी दिलाना होगा ।

महोदया, मंत्री जी इस मामले में काफी गंभीर भी हैं ।...(व्यवधान) हम सभी बुंदेलखंड की भी चिंता कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे राजस्थान की भी स्थिति वैसी है, जैसी बुंदेलखंड की है । माननीय सांसद महोदय जो संकल्प पत्र लेकर आए हैं, वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और हम सभी आपके समर्थन में हैं । आपका संकल्प पत्र पारित हो और हम तो यही चाहते हैं कि सरकार पूरी बातों को माने । हम सभी लोग आपके साथ खड़े हैं । मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में केवल 19.3 प्रतिशत कृषि भूमि ही सिंचित है, जिसमें सिंचाई का स्त्रोत केवल कुएं और बोरवेल हैं । 70 वर्षों के बाद भी पश्चिमी राजस्थान के इस कृषि प्रधान जिले में एक भी नहर या लिफ्ट केनाल परियोजना का न होना, यहां के किसानों के साथ खिलवाड़ है ।

विशेषकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 60 साल तक जो नागौर जिले को धोखा दिया, यह उसी का परिणाम है कि हम पिछड़ कर रह गए हैं । इस संबंध में आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि चंबल और ब्राह्मणी नदी के पानी को बिसलपुर तक पहुंचाने की योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और बिसलपुर से फिर नागौर की ओर पानी एक साइड से जाएगा । इस संबंध में मेरा यह आग्रह भी है कि बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा जैसलमेर को सिंचाई का पानी देने वाली इंदिरा गांधी परियोजना का लाभ भी नागौर व जोधपुर के किसानों को लिफ्ट के माध्यम से मिले तथा नर्मदा लिंक कैनाल से बाड़मेर के किसानों को नर्मदा नदी का पानी सिंचाई के लिए मिल सके ।

सभापति महोदय, अभी राजस्थान के अंदर विधान सभा चुनाव थे, तब कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी थे, अधीर रंजन जी, मैं नाम तो ले सकता हूँ न? राहुल गांधी जी वहां प्रचार में गए थे, तब उन्होंने कुंभाराम लिफ्ट की जगह कुंभकरण लिफ्ट योजना बोल दिया । फिर उन्होंने सॉरी फील कि या कि गलती

से कुंभकरण बोल दिया । जब इनको कुंभाराम और कुंभकरण में ही फर्क नज़र नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता है कि देश के विकास पर इन्होंने ध्यान दिया होगा । यह राजस्थान के अंदर उनका खुद का बयान था, बहुत बड़ा छपा था । इस परियोजना को भी जल्दी से जल्दी लागू किया जाए । मेरे एक-दो और सुझाव हैं । साबरमती का सरप्लस वॉटर जमा कर के पाली, जालौर, सिरोही आदि इन जिलों तक पहुंचाया जाए तो ये तीनों जिले इसमें जुड़ जाएंगे । नर्मदा का पानी जालौर और बाड़मेर के अंदर आए, ऐसी गुजरात सरकार से मांग करें । मंत्री जी, आप इस पर व्यक्तिगत प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमारे जालौर, बाड़मेर के अंदर भी पानी आएगा । यमुना से राजस्थान के हिस्से का जल 575 एमसीएम, ताजेवाला से चूरु, झुंझनू, सीकर इनको भी सिंचाई परियोजना से जोड़ा जा सकता है । ईआरसीपी का मुद्दा हमेशा गर्माता रहा है । पार्लियामेंट के अंदर भी और राज्य के अंदर भी हमेशा ईस्टर्न कैनाल को लेकर कांग्रेस बीजेपी के लोग बात करते रहे, लेकि न सरकारें हमेशा दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ज्यादा रही हैं । मध्य प्रदेश से राजस्थान के हिस्से का पानी ला कर 13 जिले, जिनके अंदर जयपुर, भरतपुर, कोटा डिवीजन, जिसमें लोक सभा अध्यक्ष जी का भी इलाका आता है, इस ईआरसीपी को लागू कर के कि या जा सकता है । सभापति महोदय, हमारा रामगढ़ बांध जो जयपुर के अंदर, जयपुर को भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराता है, अगर रामगढ़ बांध का जो कैचमेंट एरिया है, उससे अतिक्रमण हटाया जाए, हाईकोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि रामगढ़ बांध के अंदर जितने भी रिज़ोर्ट, होटल हैं, अभी कांग्रेस के विधायकों को जिस रिज़ॉर्ट में रुकाया गया था, वह रामगढ़ बांध के अतिक्रमण का इलाका है, जिसमें हमारे एक सांसद ने वहां धरना भी दिया था, उनको कांग्रेस की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था । रामगढ़ बांध को अतिक्रमण मुक्त कि या जाए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना की जाए । सभापति महोदय, मैं यह भी मांग करूंगा कि हमारे जो इलाके हैं, इनमें अटल भूजल योजना के द्वारा भूगर्भ जल को पुनर्पण कि या जाए, जहां ट्यूबवेल-कुओं से खेती होती है । 15 साल पहले मेरे इलाके में पानी 300-400 फीट था, आज वह 1000-1200 फीट नीचे चला गया है । पानी का लेवल ऊपर कैसे आए और दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे राजस्थान में जितने भी भूजल के ब्लॉक्स हैं, वे 75 पर्सेंट

ब्लॉक्स रिज़र्व कर दिए हैं, अब ट्यूबवेल भी वहां नहीं खुदा सकते हैं । अगर किसान की जमीन उपजाऊ है तो उसे ट्यूबवेल खुदाने के लिए अनुमति लेनी होगी और राजस्थान की सरकार अनुमति नहीं देती है । मंत्री जी, मैं इस मामले में भी आपसे निवेदन करूंगा कि जहां वॉटर लेवल 400 या 500 फीट है और गलत तरीके से राजस्थान की सरकार ने उस इलाके को प्रतिबंधित कर दिया कि यहां ट्यूबवेल नहीं खुदवा सकते हैं, तो उसमें आप यहां से आदेश जारी करें कि वॉटर लेवल अगर 1000-1200 फीट है, तो वहां तो आप ट्यूबवेल खोदने से रोको, लेकिन जहां 300 या 400 फीट है, उन किसानों को तकलीफ नहीं हो, नहीं तो वे खाएंगे क्या? उनकी जमीन उपजाऊ है । पुराने आदेश निकले हुए हैं, उसी परिपाटी पर राजस्थान चल रहा है । इसके लिए आप भूजल के अधिकारियों को निर्देश दें कि नागौर, जोधपुर के कुछ इलाके, जो प्रतिबंधित इलाके हैं, जहां आप ट्यूबवेल नहीं खोद सकते हैं, बिजली के कनेक्शन नहीं ले सकते हैं, इनकी जानकारी आप मंगवा कर दिखवाएं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत राजस्थान के किसानों को मिलेगी ।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूँगा, आप राजस्थान से आते हैं और राजस्थान के मारवाड़ इलाके से आते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा अकाल पड़े । मारवाड़ के अंदर पानी की पूरी व्यवस्था हो, राजस्थान के अंदर पानी की पूरी व्यवस्था हो । दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे नेता यहां दिल्ली में 50-60-70 साल पहले कई मंत्री भी रहें, लेकिन कभी विकास की बात उन्होंने नहीं की । प्रधान मंत्री जी ने हर व्यक्ति को जगह दी । हर बेरोजगार कह रहा है कि मोदी जी रोजगार देंगे, हर कि सान कह रहा है कि हमारे खेत में सिंचाई का पानी आएगा । आपने लोगों की उम्मीदें कश्मीर से कन्याकुमारी तक जगा दीं और वे सारे काम यहाँ पर हुए । देश ने 50-60 तक जो दंश भोगा, जो नासूर बन गया, उस नासूर को मिटाने का काम किया, खत्म किया ।

अब किसान और जवान पर सरकार को चिन्ता करनी चाहिए । प्रत्येक खेत को अगर सिंचाई का पानी मिला, तो हिन्दुस्तान विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा । इसे कोई रोक नहीं सकता । किसान अगर मजबूत हो गया, तो देश

मजबूत होगा । मैं माननीय मंत्री जी से पुन: यह माँग करूँगा । हमारे बुंदेलखंड के एमपी साहब यह संकल्प लेकर आए हैं । हमने आवारा पशुओं की बात भी की, सिंचाई की परियोजनाओं की बात भी की । जहां सिंचाई के पानी की देरी हो रही है, वहां पीने के पानी की प्रधान मंत्री जी की जो योजना है, प्रधान मंत्री जी प्रत्येक घर पर पीएम योजना का जल लेकर जाएँगे । इसमें भी उन सूखे जिले को, जो एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हमारे यहां भी ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक घर में मीठा पानी आ सकता है । इस योजना को आप लागू करे ।

मैं पुन: पुष्पेन्द्र जी के संकल्प का समर्थन करता हूँ, जिन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र की समस्याओं को रखा । मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ और पुन: माँग करता हूं कि इस पर सरकार गम्भीरता से विचार करे तथा इसे लागू करे । धन्यवाद ।

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Hon. Chairman, Sir, I rise to speak on this Bill and that may surprise some of the learned Members. Even though the matter does not concern Jammu & Kashmir, it does concern the country as a whole and also the humankind. When we go through climate change studies, we see that Central India is going to be affected most by climate change. That is why I stand in support of the hon. Member who moved this Bill.

People engaged in agriculture in Bundelkhand and other parts of Central India are under a lot of stress. They are deprived and marginalised. However, they do a huge ecoservice to the country. Therefore, irrigation facilities in Bundelkhand and adjoining areas need to be supplemented. The concerns voiced by the hon. Member are

appropriate and there is enough merit in them to persuade him to move this Bill.

Madam, we cannot lose site of the fact that people engaged in agriculture in Bundelkhand and adjoining areas are changing their cultivation patterns. By moving away from crops like rice and wheat, they are making a huge contribution to preservation of our ecosystem. We know that climate change is mostly attributable to crops like rice and wheat because of the methane gas that escapes from the rice fields. So, that way they are contributing in a big way to combat climate change. They are engaged in an ecoservice. They are doing good not only to them but also to the people in other parts of the country by moving their focus on to pulses and other crops. Therefore, I would suggest that irrigation facilities to farmers in Bundelkhand and adjoining areas and also in other parts of Madhya Pradesh need to be supplemented. This should be given top priority so that they continue to play a key role in preservation of the ecosystem and in saving from the dangers of climate change first their own region and then the whole country.

We all know that environmental disasters do not respect geographical boundaries. They do not take note of political loyalties and loyalties of communities. They affect the humankind as a whole. So, I would support the suggestions made by the hon. Member and would urge upon the hon. Minister to give top priority to supplementing and enhancing irrigation facilities in Bundelkhand and adjoining areas. Thank you.

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): धन्यवाद, सभापति महोदया । बुंदेलखंड के क्षेत्र से आने वाले सांसद कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह जी चंदेल द्वारा दिए गए इस संकल्प कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की कमी और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध न होने के कारण इस क्षेत्र में लोगों को अपनी गायें चराने के लिए खुले में छोड़ना पड़ता है, जिसे अन्ना प्रथा कहते हैं, उसके कारण से कि सानों की खड़ी फसलों को हानि होती है । इसलिए उन्होंने यह संकल्प कि जल की इस कमी की समस्या और अन्ना प्रथा से निजात पाने के लिए बांधों और तालाबों को परस्पर जोड़ना और साथ में उनके पुनर्भरण के लिए केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना से नहरों की एक प्रणाली बनाई जाए, सदन के सामने प्रस्तुत कि या है ।

महोदया, निश्चित रूप से विषय अत्यंत समसामायिक भी था, प्रासंगिक भी था और इस प्रासंगिक विषय पर श्री निशिकांत दुबे जी से लेकर के श्री हसनैन मसूदी साहब तक **21** माननीय सदस्यों ने मानसून सत्र के दौरान, शीतकालीन सत्र के दौरान और अब वर्तमान में बजट सत्र के दौरान पाँच सिटिंग्स में अलग-अलग अपने-अपने अनुभव के आधार पर विस्तार से चर्चा की । निश्चित ही संकल्प का जो विषय है और माननीय सदस्यों ने जिस तरह से अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार सदन के सामने रखे हैं, यह इस बात के परिचायक भी हैं और इस बात को बल देते हैं कि जल की समस्या, जल का संकट पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है ।

महोदया, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के कारण से भारत के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है । जल संकट, जलवायु का परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के विजिबल इम्पैक्ट्स, भारत की भूगर्भ जल पर अत्यधिक निर्भरता और उसका सिमटते जाना, लगातार भूगर्भ के जल स्रोतों का सिकुड़ते जाना, जो हमारे पारम्परिक जल स्रोत थे, उन जल स्रोतों का विलुप्त हो जाना, बढ़ती हुई आबादी के कारण से उन पर अतिक्रमण होकर के उनका अस्तित्व खो देना, इन सबके कारण से एक बहुत बड़ा संकट जल, जल संचय और जल की उपलब्धता को लेकर हो रहा है । हम सब जानते हैं, कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में विचार व्यक्त किए हैं कि जो **4** हजार बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल हमें बरसात से या बर्फ के माध्यम से प्रकृति के द्वारा उपहार

के रूप में मिलता है, आज से **70** साल पहले भी लगभग उसकी मात्रा उतनी ही थी, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है । इस 70 साल के कालखंड में हमारी आबादी जिस तरह से बढ़ी है, उसके कारण से हमारी प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता, जो एक जमाने में 5 हजार क्यूबिक मीटर से अधिक थी, वह आज घटते-घटते 1,540 क्यूबिक मीटर के लगभग पास में पहुँच गई है और वह निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के सामने एक चुनौती का विषय है । इस सबके कारण से और विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण से जिस तरह से स्कैंटी एंड इरैटिक रेनफॉल्स हो रहे हैं, एक दिन में बरसात होना और कुछ घंटों में पूरे वर्ष भर की औसत से ज्यादा बरसात हो जाना, एक जगह बरसात हो जाना, निश्चित रूप से जो मात्रा है, जब हम कुल मिलाकर कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, वह शायद पूरी हो जाती होगी, लेकिन उस जल का जिस तरह से उपयोग होना चाहिए और जिस तरह से उपयोग हो सकता है, वह नहीं हो पाता और उसके कारण से विभिन्न संकट पैदा हो रहे हैं ।

महोदया, सारे माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की, चिंता व्यक्त की कि इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव यदि कि सी पर पड़ा है तो वह गाँव में रहने वाले हमारे अन्नदाता किसान पर पड़ा है । कि सान की कृषि, जलवायु परिवर्तन और घटती हुई जल की उपलब्धता के कारण से लगातार सिमटती जा रही है, कम होती जा रही है । परोक्ष रूप में उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे गौधन, हमारे पशुधन पर भी पड़ा है, क्योंकि उनके सामने चारे का एक संकट आकर खड़ा हुआ है ।

अब कोई एक समस्या कि स तरह से दूसरी समस्या को पैदा करती है, उसका हम सबके सामने एक उदाहरण है कि बरसात की कमी के कारण कृषि के क्षेत्र में संकट हुआ । कृषि के क्षेत्र के सामने जो चुनौती आई, उसके कारण पशुधन के सामने चारे का संकट हुआ । जब चारे का संकट हुआ तो हमें मजबूरन अपने पशुओं को खुले में चरने के लिए छोड़ना पड़ा तो शेष बची-खुची जो कृषि थी, उसने उसे खा लिया और किसान के सामने एक नया संकट पैदा हुआ । कुल मिलाकर यह जो चक्रव्यूह बना, इस चक्रव्यूह ने देश की कृषि के सामने एक अस्तित्व का संकट पैदा कि या । इन सबके कारण गांव के अस्तित्व

के सामने एक चुनौती खड़ी हुई । सभी माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर अपने विचार, अपने दर्द, अपनी आशंकाएं व्यक्त कीं । मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने है और माननीय सदस्यों ने इसका जो सजीव चित्रण कि या है, वह सजीव चित्रण इस बात का परिचायक है कि गांव के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो रहा है और उसके कारण हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है । लोग गांवों से पलायन करके रोजगार की खोज में और बेहतर जीवन की खोज में गांव छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं । जब लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं तो शहरों पर जिस तरह से जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और शहरों से निकलने वाले पानी के कारण से हमारे जो बचे हुए जल स्रोत हैं, चाहे वे नदियां हों, बांध हों, झीलें हों, वे जिस तरह से प्रदूषित हो रहे हैं, वह हमारे सामने जल की चुनौती का एक और कारण बन रहा है ।

महोदया, मैं माननीय सदस्य कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी का बहुत-बहुत अभिनन्दन करना चाहता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे सम-सामयिक विषय के ऊपर इस सदन में एक संकल्प को चर्चा के लिए रखा और सारे माननीय सदस्यों द्वारा इस गम्भीर विषय पर बातचीत करने और उन सबकी चर्चा के माध्यम से हमें भी अपने मंत्रालय में काम करने के लिए, अपने मंत्रालय की पॉलिसी प्लानिंग के लिए, सरकार को अपने कामकाज की एक समीक्षा करने का एक अवसर प्रदान कि या । मैं आदरणीय पुष्पेन्द्र सिंह जी और उन सारे माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इसकी चर्चा में गम्भीरता से भाग लिया, उन सबके प्रति आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, उन सबका अभिनन्दन करना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदया, अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखीं । जनार्दन मिश्र जी ने रीवा क्षेत्र की चुनौतियों को सामने रखते हुए इस बात की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट किया कि जिस तरह से इस देश में सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक पेस्टीसाइड्स का उपयोग बढ़ रहा है और उसके कारण हमारी जमीन में सॉयल हेल्थ में जिस तरह का परिवर्तन आ रहा है, वह अपने आप में एक दूसरी चुनौती पैदा कर रहा है । उसके कारण जमीन की पर्कोलेशन कपैसिटी कम हुई । जमीन में नैसर्गिक रूप से रहने वाले जो केंचुए

थे, जो कीट-पतंगे थे, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया और उसके कारण जमीन की पोरोसिटी कम हुई । जमीन के अन्दर भूगर्भ में जो पानी समाहित होता है, वह हमारे देश में सबसे बड़े जल संसाधन या जल भंडार के रूप में है, क्योंकि our dependability for all purposes of water, whether it is for drinking, industrial use or agricultural irrigation, इन सबका 65 प्रतिशत हिस्सा भूगर्भ जल से आता है । इसके अति दोहन के कारण भूगर्भ जल जिस तरह से समाप्त हो रहा है, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कि ए ।

माननीय निशिकान्त जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए हम सबके सामने इसका एक वैश्विक परिदृश्य रखा कि किस तरह से दुनिया भर के सामने जल एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है, किस तरह से भारत के सामने जल का संकट एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है । जिस तरह से इनका अध्ययन है और सभी विषयों पर वे जिस प्रकार से बात करते हैं, उसमें उन्होंने पूरे विस्तार से यह बात रखी कि आज भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौती है और वह चुनौती प्रबंधन की कमी के कारण है । केन-बेतवा लिंक परियोजना, जिसका संदर्भ इस संकल्प में है, उस विषय में यह बात कि केन-बेतवा लिंक परियोजना कहां से प्रारंभ हुई, उस दिशा में किस तरह से विभिन्न चरणों में काम हुआ, इंटरलिंकिंग के कॉन्सेप्ट के प्रारंभ से लेकर अब तक के विषय पर विस्तार से उन्होंने सदन के सामने अपनी बात रखी ।

जगदम्बिका पाल जी और अनेक माननीय सदस्यों ने, माननीय प्रधान मंत्री जी का जो संकल्प है कि हम देश के किसान की, अन्नदाता की आमदनी को दुगुना करेंगे, इस संकल्प की मय के पीछे, इस संकल्प की सफलता के पीछे भी जल की उपलब्धता और जल संसाधनों के चरण में आने वाली कमी के कारण जो संकट खड़ा होने वाला है, उसके बारे में चिंता व्यक्त की ।

आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री अधीर रंजन जी ने भी सदन में अपने विचार व्यक्त कि ए हैं । उन्होंने भी माना कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स बहुत बड़ी चुनौती है । राज्यों के महकमों में भी इसको लेकर आपस में मतैक्य नहीं है । इसको लेकर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है । साथ ही साथ उन्होंने यह प्रश्न भी

रखा कि क्या जल के विषय को समवर्ती सूची में लाने के लिए सरकार का कोई विचार है । ऐसा प्रश्न भी उन्होंने किया था । अनेक सदस्यों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से अपने विचार व्यक्त किए । सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना निश्चित रूप से शीघ्रता से पूरी हो । हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की दिशा में, उसकी पूर्णता की दिशा में तथा उसकी सफलता की दिशा में इस माध्यम से एक कदम आगे बढ़ा सकें । बुंदेलखंड की जो परिस्थिति है, वहाँ जिस तरह से सूखे के कारण पानी की कमी है, उस परिस्थिति से बुंदेलखंड के लोगों को निजात दिया जा सकें । इस संकल्प के साथ खड़े होकर माननीय पुष्पेन्द्र सिंह जी और बुंदेलखंड की जनता का विश्वास बढ़ाने का काम सारे सांसदों ने कि या है । मैं सभी का एक बार फिर से इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ । इसके लिए मैं सभी सदस्यों का अभिनंदन करना चाहता हूँ ।

माननीय सभापति महोदया, जैसा हम सब ने अभी चर्चा में देखा और अनेक अवसरों पर सदन में इस बात के ऊपर माननीय सदस्यों ने प्रश्नों के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया, उनसे जिस किसी भी प्लेटफार्म पर बात करने का अवसर मिला, सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि इस देश में पानी का संकट एक बहुत बड़ा संकट है । यदि हम दुनिया भर के देशों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में जितना प्रकृति प्रदत्त जल हमारे पास आता है, जैसा मैंने अभी कहा कि हमारे पास जो 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी आता है, उसका हार्वेस्टेबल कम्पोनेन्ट लगभग 50 प्रतिशत जियोग्रैफिकल कंडीशन और ऑपरेशनल लॉसेस के कारण से है । जो अन्य हार्वेस्टेबल है, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त भी जो पानी हमारे पास आता है, वह लगभग 2,000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है । 2,000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स में से हम कुल मिलाकर जितना जमीन पर संधारित कर पाते हैं, वह मात्र 300 बिलियन क्यूबिक मीटर्स से भी कम है । हम पानी का ऑठवां हिस्सा भी जमीन पर रोक नहीं पाते हैं । हर साल जमीन के अंदर जो पानी रिचार्ज होता है, वह लगभग 400 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास है ।

जब मुझे एक बार माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक अवसर पर सांसदों से बात करने का एक मौका दिया था, मैंने उस दिन कुछ सांसदों से प्रश्न किया था ।

मैंने अपने मित्रों से पूछा था कि कोई मुझे बताएगा कि देश का सबसे बड़ा जल भंडार कहाँ है। सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने ज्ञान के अनुरूप बताया था। किसी ने कहा कि श्रीसैलम बाँध सबसे बड़ा है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि टिहरी का बाँध सबसे बड़ा है। जो ओडिशा के सांसद थे, उन्होंने कहा कि महानदी पर बना हुआ हमारा हीराकुंड बाँध सबसे बड़ा है। मैंने उस दिन कहा था कि इन सभी बाँधों की कुल मिलाकर जितनी क्षमता है, देश के सबसे बड़े बाँध से लेकर गाँव के सबसे छोटे पोखर, जिसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, यदि इन सभी को जोड़ दीजिए तो उससे दोगुना जल हमें भूगर्भ का भंडार देता है।

पिछले 40 सालों में हमारा जितना भी इरिगेशन का एक्सपैंशन हुआ है, उसका 85 प्रतिशत हिस्सा हमको जमीन के पानी से मिलता है। दुनिया भर के ऐसे बहुत सारे देश हैं, हमारे ऊपर प्रकृति की कृपा है कि लगभग 1168 मिलीमीटर बरसात हमारे यहाँ एवरेज रेन फॉल होता है। दुनिया में इजराइल का उदाहरण भी हमारे सामने है, जहाँ लगभग 100 मिलीमीटर बरसात होते हुए भी वह आज जल समृद्ध देश है। उन्होंने जिस तरह से जल का प्रबंधन कि या कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी का उपयोग कि स तरह से कर सकें, वर्षा के जल का ज्यादा से ज्यादा संचय कि स तरह से कर सकें, पानी का पुन: उपयोग कि स तरह से कर सकें और जुडिशियस यूज ऑफ वाटर करें। हम पानी की एक-एक बूंद को बचाते हुए अधिकतम उपयोग कि स तरह से कर सकें, इस दृष्टिकोण से जब उन्होंने काम कि या तो आज अपने देश को जल सुरक्षित बनाया। मुझे लगता है कि हम सभी को भी निश्चित रूप से इस दिशा में चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारी जो चुनौती है, उस चुनौती का अगर समग्र रूप से कोई एक समाधान है तो वह यह है कि हम जल प्रबंधन की दिशा में मिलकर काम करें।

माननीय सभापति महोदया, चूंकि जल का विषय संविधान प्रदत व्यवस्था के अनुरूप राज्यों का विषय है, इसलिए प्राथमिक रूप से राज्यों को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। केन्द्र की सरकार भी इस महत्वपूर्ण विषय पर वर्षों से काम कर रही है। जब-जब भी सरकारें बनीं, अपने-अपने दृष्टिकोण से

इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए प्रयास किए गए । एक राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण किया गया है । इस राष्ट्रीय जल नीति में जल प्रबंधन और संचय करने के लिए बेहतर तरीके से हम कि स तरह से काम कर सकते हैं, उस नीति का मार्गदर्शन प्रदान किया गया ।

हम जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सप्लाई साइड मैनेजमेंट पर कि स तरह से काम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी को किस तरह से रोक सकते हैं, इसके बारे में मार्गदर्शन राष्ट्रीय जल नीति द्वारा दिया गया है । मैं मानता हूं कि आज समय आ गया है कि हम केवल सप्लाई साइड मैनेजमेंट से देश को जल के संकट से नहीं उबार सकते हैं, हमें साथ ही डिमांड साइड मैनेजमेंट पर भी काम करना होगा । हमें जल के अधिकतम उपयोग पर निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा ।

मैंने पहले भी इस सदन और राज्य सभा में निवेदन किया था । कृषि में जल का उपयोग प्रोडक्टिविटी के आधार पर देखें तो दुनिया का सबसे कम प्रोडक्टिव पानी भारत में है । विभिन्न स्टडीज़ इस बात को उल्लिखित करती हैं कि एक किलोग्राम चावल उगाने के लिए भारत में 5600 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि चीन से लेकर अनेक देश केवल 350 लीटर पानी में एक किलो चावल उगाते हैं । हम सबको निश्चित रूप से इस पर विचार करने की जरूरत है ।

ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक नहीं हैं । मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, यहां माननीय कृषि राज्य मंत्री जी बैठे हैं । इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साइंटिस्ट्स का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, उन्होंने यह विधा बहुत साल पहले विकसित कर ली थी । कृषि राज्य का विषय है, टेक्नोलॉजी का डिसेमिनेशन धरातल तक कि सानों तक पहुंचे, इसकी प्रमुख रूप से जिम्मेदारी राज्य की है, इसलिए राज्य सरकारों को देखना चाहिए कि क्या उगाएं, कैसे उगाएं और कैसे एक-एक बूंद पानी का उपयोग करें ।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के सामने संकल्प रखा – 'per drop, more crop', इसके साथ हम किस तरह से काम करें ताकि हम कम से कम पानी का उपयोग करके अधिक पानी बचा सकें और आने वाली पीढ़ियों को जल सुरक्षित, जल समृद्ध भारत दे सकें । हमने इस दृष्टिकोण से नीति बनाई, विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राष्ट्रीय जल नीति का एक बार पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है, दोबारा देखने की आवश्यकता है । हमने इस दृष्टिकोण से 5 नवंबर, 2019 को एक नई समिति का गठन करके राष्ट्रीय जल नीति में व्यापक संशोधन करते हुए और इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने की दिशा में काम किया है ।

हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के ठीक बाद पहली बार माननीय प्रधान मंत्री जी ने रेडियो में 'मन की बात' के माध्यम से पूरे देश को संबोधित किया । उन्होंने विस्तार से देश के सामने संकल्पना रखी कि हम किस तरह से देश को इस गंभीर संकट से बचा सकते हैं । उन्होंने गांवों के लोगों से आग्रह किया, गांवों के प्रधानों से आग्रह किया कि हम कैसे अपने गांव में बरसात के पानी की एक-एक बूंद का संरक्षण कर सकते हैं, जल संचय कर सकते हैं ताकि गांव का पानी गांव में रहे, खेत का पानी खेत में रहे । इसके साथ ही बताया कि घर का पानी घर में किस तरह संचित कर सकते हैं । हम सबको इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है । जब उन्होंने इस दृष्टिकोण से बात की तो निश्चित रूप से एक वायुमंडल का निर्माण हुआ ।

यह जल का विषय है । सरकार की गंभीरता आप सब लोगों और माननीय सदन के सदस्यों के संज्ञान में आई होगी कि जल के विषय के बारे में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अलग डिपार्टमेंट्स, डिवीजन्स में विचार हुआ, पॉलिसी प्लानिंग हुई, निर्णय हुए । माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बार एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया । देश के जल के विषय से जुड़े विभागों और लगभग सब मंत्रालयों को इन्टीग्रेट करके नए मंत्रालय का गठन किया । देश के सामने एक नया संदेश दिया कि अब हम जल जैसे महत्वपूर्ण विषय को एक साथ समग्र और हालिस्टिक रूप से निर्णय करके पॉलिसी प्लान करें ताकि भविष्य में लोगों को जल समृद्ध देश दे सकें ।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक पत्र लिखकर देश भर के चुने हुए गांव के प्रतिनिधियों को पत्र लिखा । उन्होंने ढाई लाख लोगों को बारह भाषाओं में पत्र लिखकर अपनी तरफ से संदेश दिया कि जिस तरह से गांव में पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन करते हैं, उसी तरह एक डेडिकेटेड ग्राम सभा केवल जल के विषय में हो कि किस तरह से गांव में जल का उपयोग कैसे करें, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट करते हुए गांव के पानी का अधिकतम उपयोग कैसे करें, गांव को जल सुरक्षित और जल समृद्ध किस तरह से बनाएं, इस पर गांव के सब लोग बैठकर विचार करें । मुझे सदन के सामने यह बात कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि डेढ़ लाख से ज्यादा पंचायतों ने माननीय प्रधान मंत्री जी के इस आह्वान का अनुसरण किया, सब लोग साथ जुटे, साथ बैठे और कुछ कदम इस दृष्टिकोण से इस दिशा में आगे बढ़ाए । मैं मानता हूं कि जो पहला कदम रखा जाता है, वही सफलता का मार्ग सुनिश्चित करता है ।

पहला कदम डेढ़ लाख पंचायतों ने रखा । आज पूरे देश भर में एक वायुमंडल का निर्माण हुआ है । पूरे देश भर में लोगों ने इस बारे में चर्चा करना प्रारंभ किया, चिन्तन करना प्रारंभ कि या और विचार करना प्रारंभ किया । जैसे माननीय प्रधान मंत्री अक्सर कहते हैं कि ऐसी सारी चुनौतियों का समाधान तभी हो सकता है, जब ये चुनौतियां एक जन चर्चा और जन आंदोलन का विषय बने । जल के आंदोलन को जन-जन का आंदोलन बनाने की दिशा में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमने सफलता प्राप्त की है । जल शक्ति अभियान के माध्यम से ऐसे 256 जिले, जैसे मैंने अभी चर्चा में कहा कि हमारी अधकि तम 65 प्रतिशत निर्भरता भूगर्भ के जल में है । देश के पश्चिमी हिस्से में, यदि भारत के नक्शे को रखा जाए तो कश्मीर से लेकर केरल तक लगभग पूरे पश्चिमी हिस्से में ऐसे जिले आते हैं, जो सूखे से ग्रस्त हैं या वहां की जमीन में पानी की कमी है । जहां जमीन के पानी के भंडार समाप्त हो रहे हैं या जमीन के पानी के भंडार सिकुड़ते जा रहे हैं, देश भर में 6800 से ज्यादा ब्लॉक्स हैं, जिनको हम पीरियोडिकली मॉनिटर करते हैं, उनमें से लगभग 1500 ब्लॉक्स ऐसे हैं, जो या तो एक्सप्लॉएटेड हैं या ऐसे ब्लॉक्स हैं जो क्रिटिकली एक्सप्लॉएटेड अथवा सेमी क्रिटिकल कंडीशन में हैं । यदि जिलों के ऐसे सारे ब्लॉक्स को चिह्नित किया जाए

तो इन जिलों में से जिनको वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स कह सकते हैं, ऐसे 256 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया है । कुछ प्रदेशों में ऐसे जिले हैं जो उस प्रदेश में क्रिटिकली एक्सप्लॉएटेड, ओसीएस कैटेगरी या वाटर स्ट्रेस्ड कैटेगरी में नहीं आते होंगे । ऐसे जिले हरेक प्रदेश में हैं, जहां कहीं न कहीं इस प्रकार का काम होता है कि समग्र रूप से इस तरह की हलचल बने, एक देशव्यापी परिकल्पना बने और इसके ऊपर देशव्यापी विचार हो, इस दृष्टिकोण से 256 जिले आइडेंटिफाई किए गए । भारत सरकार में संयुक्त सचिव और उनके ऊपर के स्तर के अधिकारी, सीडब्ल्यूसी के इंजीनियर्स, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के हाइड्रो जियोलॉजिस्ट, इन सबको साथ में भेजकर तथा जिलों में कलक्टर को नोडल ऑफिसर बना करके एक रिपल क्रिएट करने के लिए इस अभियान को प्रारंभ किया गया । देश को दो हिस्सों में इन 256 जिलों में बांटा, एक जहां मानसून पहले आता है और दूसरा, जहां दूसरे दौर का मानसून आता है । ऐसे जिलों को हमने आइडेंटिफाई कि या और वहां इन अधिकारियों ने दो-तीन विजिट्स किए । उनको मैनडेट दिया गया था कि वे जल संरक्षण के ऊपर और उस जिले में वर्षा जल का संचयन कैसे हो सकता है, उसके बारे में व्यापक विचार-विमर्श करके लोगों को उसके बारे में जागृत करें तथा जन जागृति के लिए काम करें । वहां के परंपरागत जो जल संसाधन हैं, जैसे-तालाब, बावड़ियां, जोहड़, झीलें आदि, उन सबका पुनरुद्धार कैसे हो सकता है, उनको किस तरीके से जीवित किया जा सकता है, उसकी व्यापक योजना बने । ऐसे बोरवेल्स जो इन क्षेत्रों में ड्राइ हो गए हैं, जो हैंड पंप्स ड्राई हो गए हैं, उनका वर्षा जल पुनर्भरण के जरिये कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसकी रचना करें, इसके बारे में लोगों से चर्चा करें ।

वारटशेड विकास पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं? इन जिलों में उसके ऊपर व्यापक योजनाएं बनें । इन सबके साथ-साथ, जिस विषय के बारे में हम बार-बार करते हैं, पेड़-पौधे लगाना, बरसात को आमंत्रित करना और उसके माध्यम से भूगर्भ के जल का संचयन करना अत्यंत आवश्यक है । इन जिलों में ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन कैसे हो सके, उसकी योजना बनाएं ।

मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से एक अत्यंत सफल कार्यक्रम के रूप में पहचाना गया । अनेक सांसदों ने जिनके जिले उन

256 की सूची में नहीं थे, मुझे आग्रह किया कि हमारे जिलों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। हमने राज्य सरकारों को लिखा, हमने अपने सांसद मित्रों से भी निवेदन किया कि आप चाहें तो इस तरह का कार्यक्रम अपने प्रदेश में सारे जिलों में ले सकते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, जिसने माननीय प्रधान मंत्री जी के आह्वान पर जल शक्ति मंत्रालय, जिस तरह देश की सरकार में एक इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बनाई गई है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में न केवल इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बनाई गई अपितु उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जल शक्ति अभियान को अपने स्तर पर लेकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जो राज्य देश की सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण के लिए, वर्षा जल संचयन के लिए और वाटरशेड के लिए जिस तरह से काम होता है, उन सबको एक साथ जोड़कर हम इंटीग्रेटेड रूप में किस तरह से प्रयास कर सकते हैं, किस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकते हैं, इसका एक नायाब उदाहरण इस जल शक्ति अभियान के माध्यम से देखने को मिला। हजारों संरचनाएं बनाई गईं और हजारों संरचनाओं को, जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज थे, उन सबका पुनरुद्धार करने के लिए इस दिशा में योजनाएं बनीं और व्यापक रूप से सफलता के साथ उस दिशा में काम हुए।

जल शक्ति अभियान के माध्यम से दो लाख से ज्यादा जल संचयन संरचनाएं बनाई गईं। इसके अलावा अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो पिछले पांच सालों में नरेगा के माध्यम से 31907 करोड़ रुपये केवल वॉटर हार्वेस्टिंग और नेचुरल रिर्सोस मैनेजमेंट के ऊपर खर्च किया गया। 18,760 करोड़ रुपये केन्द्रीय हिस्से के रूप में राज्यों को वॉटरशेड मैनेजमेंट के लिए प्रदान किए गए। मैं मानता हूं कि हमें अपेक्षित सफलता इन कार्यक्रमों के माध्यम से मिलनी चाहिए। राज्यों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इसे इंप्लीमेंट किया है, लेकि न सांइटिफिक बैकअप नहीं होने के कारण से जितना इम्पैक्ट इतनी बड़ी राशि के खर्च होने से बनना चाहिए था, उतना शायद नहीं बन पाया। हमने नरेगा के माध्यम से नेचुरल रिर्सोस मैनेजमेंट और विशेष रूप से जल के विषय पर जो पैसा खर्च किया गया है, उसका अध्ययन करवाया है। जो वॉटर स्ट्रेस्ड एरिया है, यदि हम एक-दूसरे लक्ष्य को सुपर इंपोज करें तो बहुत सारा गैप

दिखाई देगा । बहुत सारी जगहों पर ऐसी परिस्थितियां है, जहां पर वर्षा जल के पुनर्भरण और जमीन में जल के पुनर्भरण के लिए अलग तरह की अवसंरचनाओं की आवश्यकता है । जमीन के अन्दर की स्ट्रेटा स्टडी न होने के कारण से वह काम उतनी सफलतापूर्वक नहीं हो पाया है ।

सभापति महोदया, मैं आज आपके माध्यम से सदन को प्रसन्नता से यह बात साझा करना चाहता हूं कि देश की सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐक्कफर की स्टडी की है । जमीन के अन्दर कि स तरह की भौगोलिक संरचना है और हम किस तरह की अवसंरचनाएं बनाकर जमीन के अन्दर पानी को ज्यादा तेजी से भर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से हमने काम करना प्रारम्भ किया है । आज देश भर में 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन का अध्ययन या ऐक्कफर का अध्ययन करना है, उसमें से 11 लाख 40 हजार स्क्वायर कि लोमीटर का अध्ययन करके उनकी प्लानिंग कर दी गई है । हर एक जिले की अपनी-अपनी स्टडीज बनाकर इस तरह के प्लान तैयार कर दिए गए हैं और हमने उनको राज्यों के साथ साझा किया है, ताकि हम जो नरेगा या वॉटर शेड मैनेजमेंट के माध्यम से खर्च करने वाले हैं, उसको आने वाले समय में और ज्यादा साइंटिफिक बैकअप के साथ कर सकें, ताकि उसके अच्छे परिणाम तीव्रता के साथ प्राप्त हो सके ।

माननीय सभापति महोदया, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाया है । अभी आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देश के किसान का अधिकार है कि पानी उसके घर और खेत तक पहुंचना चाहिए । माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत लंबे समय से लंबित परियोजनाएं पड़ी थीं, जिन परियोजनाओं पर लगातार पिछले 25-30 सालों से काम चल रहा था । 60 से 70 प्रतिशत तक परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं, लेकिन उन योजनाओं में कुछ छोटी-छोटी कमियों के कारण से, राज्यों के पास धन की उपलब्धता न होने के कारण से, संसाधनों की सीमितता के कारण से, वे योजनाएं लंबित पड़ी हुई थी । माननीय प्रधान मंत्री जी ने ऐसी 99 योजनाओं को चिह्नित करवाया । हमने उन 99 परियोजनाओं पर काम शुरू किया और आज मैं प्रसन्नता से कह सकता हूं कि हमने उनमें से 40

परियोजनाओं पर काम पूरा कर लिया है और शेष 40 परियोजनाओं का भी शीघ्र काम पूरा हो जाएगा । हमने तेजी के साथ कार्य प्रारम्भ किया और उसके कारण ही आज मैं प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि 76 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की क्षमता बढ़ी है, या अभिवृद्धि हुई है या हम उसमें इफैक्टिव रूप से सिंचाई कर पाने की स्थिति में पहुंचे हैं ।

माननीय सभापति महोदया, मैंने अभी जैसा कहा है कि हम केवल सप्लाई साइड के मैनेजमेंट को करते हुए इस देश को जल समृद्ध नहीं बना सकते हैं । हमको डिमाण्ड साइड मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा । मैंने कहा है कि हम नई राष्ट्रीय जल नीति की कल्पना करते हैं, उसमें हमने बराबर का बल देने की दिशा में काम करना प्रारम्भ किया है । माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार इस देश में एक 'अटल भूजल योजना' के माध्यम से गत 25 दिसम्बर को देश के नेता स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर एक नई योजना का प्रारम्भ किया है, जिसमें 7 राज्य वॉटर स्ट्रेस्ड थे । हमने उन 7 राज्यों के 78 जिलों को चिह्नित कि या और उन 78 जिलों के लिए प्रायोगिक रूप से 6 हजार करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है, जिसमें से 3 हजार करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक के माध्यम से मिलने वाले हैं ।

माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, वहां कि स तरह से सप्लाई साइड मैनेजमेंट के साथ-साथ डिमाण्ड साइड मैनेजमेंट पर काम कर सकते हैं, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट के माध्यम से, जन सहयोग माध्यम से लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करके, कैसे उनको जल समृद्ध बना सकते हैं, इस दृष्टिकोण से हमने काम करना प्रारम्भ किया है । इन 78 जिलों में अनुकूल परिणाम आने के बाद, इसको आगे और विस्तार देते हुए, देश के हरेक हिस्से में यह काम करेंगे कि किस तरह से लोगों को साथ जोड़कर जल समृद्ध बना सकते हैं । ऐसे अनेक उदाहरण देखने में आते हैं, मैंने इज़राइल की बात की, यदि मैं इज़राइल को छोड़ दूं, हमारे देश में भी अनेक ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलती हैं । राज्यों के द्वारा की हुई सक्सेस स्टोरीज के बारे में मैंने कल यहां सदन में उत्तर देते हुए कहा था कि अनेक प्रदेशों ने इस दृष्टिकोण से काम किया है । गुजरात की सरकार ने सुजलाम सुफलाम योजना शुरू की और जब माननीय प्रधान मंत्री

जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने वहां जिस तरह से काम कि या, महाराष्ट्र सरकार ने जलयुक्त शिवार नाम से योजना बनाकर काम किया । राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने मुख्य मंत्री जल स्वालम्बन योजना के माध्यम से काम किया, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नीरू चेट्टू मिशन, तेलंगाना सरकार ने मिशन काकतीया बनाकर काम किया । हरेक राज्य ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इन योजनाओं पर काम किए हैं । बिहार सरकार वर्तमान में जल जीवन हरियाली नाम के शीर्षक के साथ इस दिशा में काम कर रही है । अनेक राज्यों सरकारों ने इस तरह से काम किए हैं और उनके निश्चित रूप से अनुकूल परिणाम आए हैं ।

यदि सरकारों की बात भी छोड़ दें, जो कम्यूनिटी लैड आर्गनाइजेशन्स हैं, एनजीओज आदि ने भी ऐसे बहुत से काम किए हैं । महाराष्ट्र में जय भारती जैन संघटना के लोगों ने काम कि ए । इस तरह के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जहां कम्यूनिटी या एनजीओ के लोगों ने मिलकर काम किए हैं और उनके अनुकूल परिणाम आए हैं । गांव के लोगों ने ग्राम पंचायत में बैठकर काम कि या । एक व्यक्ति, एक सरपंच खड़ा हुआ, उसने अपने संकल्प के साथ जब गांव में काम करना शुरू किया, जब गांव के लोगों की जनभागीदारी उसके साथ जुटी, प्रत्येक व्यक्ति जब उसके साथ खड़ा हुआ, तब उस गांव में कायाकल्प हुआ । हिवड़े बाजार का उदाहरण हमारे सामने है, रालेगण सिद्धी का उदाहरण हमारे सामने है । राजस्थान के एकदम सूखे इलाके पिपलांतरी का उदाहरण हमारे सामने है । ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जहां गांव के लोगों ने हाथ में कमान उठाई और उस गांव का कायाकल्प हुआ । केवल एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और उसने काम करना प्रारम्भ कि या । मैं राजस्थान से आता हूं, जयपुर के पास दौसा जिले में एक छोटा सा गांव है – लापोड़िया । उसके आस-पास के गांवों में भी कहीं एक बूंद पीने का पानी नहीं था । जमीन का पानी इतना खारा था कि पीने के लिए किसी भी तरह से उसका उपयोग नहीं कि या जा सकता था और जमीन में पानी उपलब्धता भी बहुत कम थी । वहां लक्ष्मण सिंह नाम का लगभग बिना पढ़ा-लिखा आदमी खड़ा हुआ और उसने अपने गांव में, अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अपने खेत में ऐसी अवसंरचनाएं बनाईं, जिनको चौका नाम दिया गया । उस चौका सिस्टम में खेत के ग्रेडिएंट्स देखकर, उसने खेत में

एक फुट गहरे, दस या बारह फुट चौड़े और बीस या तीस फुट लम्बे गढ्ढे खोदकर वर्षा के पानी को संग्रहीत किया । उसको कुछ अनुकूलता मिली तो गांव के दूसरे लोग प्रेरित हुए और उन्होंने साथ मिलकर इस तरह से काम किया । आज मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि न केवल लापोड़िया जल समृद्ध हुआ, आज उस गांव के कि सान तीन चक्र की फसल एक वर्ष में ले रहे हैं । उसके आस-पास के 58 गांव जल समृद्ध हुए हैं । दुनिया इज़राइल की बात करती है, मैंने भी प्रारम्भ वहां से किया, लेकिन इज़राइल के वैज्ञानिकों ने वहां आकर शोध किया और उस टेक्नोलॉजी को इज़राल में लागू करने का काम किया । देश में अनेक लोगों ने इस दिशा में काम किया है । यदि देश को जल समृद्ध बनाना है, तो हम सभी को पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट की दिशा में जाना पड़ेगा । हमने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में अटल भूजल योजना के माध्यम से इस दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाया है ।

महोदया, पीने के पानी के संकट के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने बात की । पीने के पानी के संकट के बारे में पुष्पेंद्र सिंह चन्देल जी ने विस्तार से बात की । उन्होंने कहा कि पीने के पानी का गंभीर संकट हमारे सामने है । यहां निहाल चन्द जी बैठे हैं, वह नहरी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन इनके यहां क्वालिटी ऑफ वाटर की वजह से गंभीर चुनौती है । ...(व्यवधान)

श्री निहाल चन्द (गंगानगर): मंत्री जी, मैं नहरी क्षेत्र से आता हूं, लेकिन वहां हम लोग जिस तरह से गन्दा पानी पी रहे हैं, उससे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आप अंदाजा लगा सकते हैं ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सभापति जी, मैं निहाल चंद जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं । इस देश में पिछले पांच साल सामान्य आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने काम किया है । कि सी ने कल्पना नहीं की थी कि देश का प्रधान मंत्री लाल किले के प्राचीर से यह बात कहेगा कि

देश के प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए । केवल सैनिटेशन के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और साधारण मानव के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यह घोषणा माननीय प्रधान मंत्री जी ने की थी । जब उन्होंने यह घोषणा की, उसके बाद सदन की दीवारें साक्षी होंगी, अनेक बार अनेक तरह के प्रश्न खड़े कि ए गए और अनेक तरह की आशंकाएं व्यक्त की गईं । मुझे याद है कि ब्लूमबर्ग ने कि स तरह के आर्टिकल लिखे थे और बीबीसी ने कि स तरह के आर्टिकल लिखे थे । सभी ने इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की थीं कि देश में यह संभव नहीं है कि पांच साल के कालखंड में, जो देश दुनिया का **60** प्रतिशत ओपन डेफिकेशन वाला देश है, वह देश ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाएगा । लेकि न संकल्प की शक्ति थी, राजनीतिक नेतृत्व की संकल्प शक्ति थी और माननीय प्रधान मंत्री जी की ड्राइविंग फोर्स थी, पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ और आज जब हम **135** करोड़ लोग कह सकते हैं कि हमने देश को सौ प्रतिशत स्वच्छ देश, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है । साधारण मानव के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए गैस का चूल्हा दिया । साधारण मानव के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमने देश के हर गरीब को आवास देने के दृष्टिकोण से काम करना प्रारम्भ कि या । हर साधारण मानव के घर में भी बिजली का कनेक्शन हो, हजारों गांव जो बिना बिजली के थे, उन सभी घरों में बिजली पहुंचे, इस दृष्टिकोण से काम करना प्रारम्भ किया । हर घर तक बैंक खाता पहुंचे और इन सब के माध्यम से साधारण मानव के जीवन में परिवर्तन लाना और उसके साथ-साथ महिलाओं का सम्मान और उनके सशक्तीकरण करने का काम हमारी सरकार ने कि या और उस दिशा में एक और कदम बाकी था, जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी पीड़ा का कारण है कि देश के प्रत्येक घर में पीने का पानी पहुंचे ।

महोदया, आजादी के पहले से प्रयास प्रारम्भ हुए थे और आजादी के **70** सालों बाद देश में 18 करोड़ के लगभग जो ग्रामीण आवास हैं, उनमें से केवल तीन करोड़ घरों तक हम पीने का पानी पहुंचा पाए थे । केवल तीन करोड़ घरों तक हम पीने का पानी नल के माध्यम से स्वच्छ पानी पहुंचा पाए थे । आजादी के 70 सालों में केवल 18 प्रतिशत तक पहुंचे थे और एक बार फिर देश के प्रधान

मंत्री जी ने लाल कि ले की प्राचीर से संकल्पना की और देश के सामने यह संकल्प रखा कि हम आने वाले पांच सालों में, वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण आवास तक नल से जल पहुंचाने का काम करेंगे । हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने की दिशा में हम काम करेंगे और मैं आज आप सभी के सामने विश्वास से कह सकता हूं कि पिछले दिनों हमने जिस तरह से इस दिशा में काम प्रारम्भ किए, राज्यों के साथ बैठकर जिस तरह से चर्चाएं कीं और राज्यों को जिस तरह से वित्तीय सहयोग देने का हमने वायदा किया है, कई राज्यों ने बहुत तेज गति से उस दिशा में काम करना प्रारम्भ कर दिया है । कुछ राज्य हैं, जहां इस काम में गति मिलना बाकी है और जिस गति से काम करना अपेक्षित था, वह गति नहीं मिल पाई है । कुछ राज्य ऐसे हैं, जो अपने संसाधनों के सीमित होने की बात कहते हैं और उस दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं । मुझे बहुत दुख होता है, जब मैं यह बात लोगों के सामने बैठकर करता हूं और बैठकों में समीक्षा की बात करता हूं कि मेरा अपने राज्य राजस्थान में, जहां हमने **1600** करोड़ रुपये दिये, वहां सबसे कम खर्चा हुआ और इस दिशा में सबसे कम प्रगति हुई । कुछ राज्यों ने बहुत कमिटमेंट के साथ इसमें काम करना प्रारम्भ किया है और उन राज्यों ने संकल्प कि या है । मैं उत्तर प्रदेश की सरकार का उल्लेख करना चाहता हूं । वहां के माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह तय कि या है कि वर्ष **2021** तक प्रदेश के प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने के लिए काम करेंगे । झारखंड की सरकार ने भी पहले इस दिशा में काम कि या था, लेकि न अब कुछ विराम लगा है । मुझे लगता है कि शायद कुछ गति आने वाले समय में बढ़ेगी । 'जल जीवन मिशन' के माध्यम से हम न केवल पीने का पानी पहुंचाएंगे, अपितु हमारी मातृ शक्ति, हमारी माताएं-बहनें जिन्हें पीने का पानी लेने के लिए रोज मीलों पैदल चलना पड़ता है, उन्हें भी इससे फायदा पहुंचेगा ।

महोदया, मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं और पश्चिमी राजस्थान का भी सुदूर रेगिस्तान का हिस्सा है । मेरे मित्र कैलाश जी बैठे हैं । इनके लोक सभा क्षेत्र में और मेरे लोक सभा क्षेत्र में शायद बहुत सारे ऐसे गांव होंगे, जहां की महिलाओं को 12-13 साल की उम्र से 65-70 साल की उम्र तक प्रतिदिन अपने सिर पर पानी के दो-दो मटके रखकर लाना होता है । वे जितने कि लोमीटर रोजाना पानी

के लिए चलती हैं, पानी के लिए जीवनपर्यंत जितना चलती हैं, आप महिला होने के नाते उनका दर्द समझ सकती हैं कि वे जितने कि लोमीटर पूरी उम्र पानी लाने के लिए चलती हैं, यदि एक दिशा में उतना चलना प्रारम्भ करें तो शायद वे पूरी धरती के दो चक्कर अपने जीवन में लगा लेतीं । महिलाओं के साथ इतनी बड़ी जो ट्रेजडी हो रही है, उससे मुक्त करने की दिशा में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमने 'जल जीवन मिशन' के माध्यम से काम करना प्रारम्भ किया है । जैसा मैंने कहा कि हमारी अधिकतम निर्भरता भूगर्भ के जल पर है और भूगर्भ के जल संसाधनों को हम कि स तरह से, जो अति दोहित हैं और लगातार जहां पानी की कमी हो रही है, वहां ध्यान देने की है । भूगर्भ का जल इनविजिबल सोर्स है, वे दिखाई नहीं देते हैं और दिखाई न देने के कारण जमीन के पानी को हम लगातार जिस तरह से अतिदोहित कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से देश के सामने बड़ी चुनौती और चिंता का विषय है । बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अथाह भूजल था लेकिन आज उन जगहों पर पीने का पानी भी नहीं है और पीने का पानी भी दूसरी जगह से लाकर वहां के लोगों को पिलाना पड़ रहा है ।

<u>17.00 hrs</u>

ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हम सब लोगों के परिवेश में कहीं न कहीं होंगे । निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी चुनौती है । भूगर्भ के जल की जिस तरह से क्वॉलिटी अफैक्ट हो रही है, आर्सेनिक का प्रभाव बढ़ रहा है, फ्लोराइड का प्रभाव जिस तरह से भूगर्भ के जल में बढ़ रहा है, यह सब चिंता का विषय है । पर हमने इस दिशा में कि हम भूगर्भ के जल को किस तरह से दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, इस दिशा में भी हमने व्यापक योजना के साथ काफी तेजी के साथ काम करना प्रारम्भ किया है । जैसा मैंने कहा कि हमारी 65 प्रतिशत आवश्यकता भूगर्भ के जल से पूरी होती है, मैं आज भी कहीं चर्चा कर रहा था । हमारे बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य बैठे थे । उन्होंने कहा कि हमने तय किया कि अपने घर में हम पानी बचाएं । निश्चित रूप से सब लोगों ने इस दिशा में सोचना प्रारम्भ किया है ।

मैं आप सबके साथ एक संस्मरण साझा करना चाहता हूं । कुछ दिन पहले मैं हवाईजहाज से मुम्बई से दिल्ली आ रहा था । इंडिगो का हवाईजहाज था । मेरे

साथ एक महिला और उनकी एक छोटी सी बच्ची बैठी थी । एयरहोस्टेस ने लाकर पानी का गिलास दिया । मैंने अपना पानी पिया और पानी का गिलास तोड़कर सामने पॉकेट में रख दिया । उस छोटी सी बच्ची ने भी दो तीन बार में पानी का गिलास पीकर अपने गिलास को समाप्त किया । उनकी माता जी ने एक घूंट पीकर पानी का गिलास रख दिया । थोड़ी देर में जब एयरहोस्टेस सामान इकट्ठा करने के लिए आई तो हम सबने गिलास दिया, उनकी बच्ची ने भी गिलास डाला और उनकी माता जी जब आधे से ज्यादा पानी से भरा गिलास उसमें डालने लगी तो बच्ची ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि नहीं, मम्मा, "Mummy, you cannot waste water." मोदी जी ने मना किया है । पांच साल की बच्ची इस दिशा में सोचने लगी । निश्चित रूप से यह एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में है कि लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है ।

जब व्यवहार चेंज होता है और सोच में बदलाव आता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है । लेकिन हम घर में जितना पानी उपयोग करते हैं । उन्होंने कहा है कि हमने घर में तय किया है कि हम घर में कम से कम पानी उपयोग करेंगे लेकि न कुल मिलाकर जितना पानी हम साल भर में उपयोग करते हैं, उसका छः प्रतिशत पानी हम घरेलू उपयोग के लिए लेते हैं । पांच प्रतिशत पानी हम इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं । 89 per cent of the total water we use is being used in agriculture. निश्चित रूप से, जैसा मैंने कहा कि हमारा पानी लीस्ट प्रोडक्टिव पानी ऐसा दिखाई देता है । मैं सारे माननीय सदस्यों और सारे राज्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने परिवेश में किसानों को जागृत करने का काम करें कि हम किस तरह से कम से कम पानी का उपयोग करके, सही फसल का उपयोग करें । किस जगह के लिए किस फसल की आवश्यकता है और उसी फसल को हम उगाएं ।

मैं हरियाणा की वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने जब अपने यहां योजना ली क्योंकि हरियाणा में चावल पारम्परिक रूप से पहले नहीं उगाया जाता था । लेकिन आज हरियाणा में अधिकतम किसान चावल उगा रहे हैं । चावल उगाने के लिए किसान को दूसरी फसल के लिए शिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना भी एक काम है । हरियाणा के मुख्य मंत्री जी ने एक योजना

बनाई कि जो किसान चावल की जगह मक्का उगाएगा, हम सौ प्रतिशत उसकी मक्का की फसल का प्रोक्योरमेंट करेंगे । इसके साथ ही उसको 2-2500 रुपए प्रति एकड़ का इंसेंटिव भी देंगे । एक जिले में प्रायोगिक रूप से इसको प्रारम्भ किया । एक महीने में 18000 से ज्यादा हेक्टेअर ज़मीन इस पर ट्रांसफर हुई । कुल मिलाकर 1 लाख ज़मीन में चावल से मक्का ट्रांसफर करने की तरफ हमें सफलता प्राप्त हुई है । ऐसे प्रयोग शायद कुछ और प्रदेशों में भी हुए होंगे ।

पंजाब ने भी अपने यहां एक योजना प्रायोगिक रूप से प्रारम्भ की है । लेकिन सब प्रदेशों को और हम सबको क्योंकि हम सब अपने-अपने क्षेत्र में अपने लोगों के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं । हम उनका नेतृत्व करते हैं । आवश्यकता है कि हम कि सानों को भी इस दिशा में जागृत करें कि वे कि स तरह से मिनिमम पानी के उपयोग से कि स समय में कौन सी फसल उगाएं ।

जो वॉटर एफिशिएंट इरीगेशन के लिए, स्प्रिंक्लर्स और ड्रिप इरीगेशन के लिए सरकार जो सहायता मुहैया कराती है और बुंदेलखंड के लिए भी सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से कुछ उपाय किए हैं जिसमें बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, लघु और सतही परियोजना, छोटे तालाबों के निर्माण के लिए और उन निकायों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की दिशा में हमने काम करना प्रारम्भ किया है ।

महोदया, जिस एआईबीपी के कार्यक्रम की मैंने चर्चा की है, उस कार्यक्रम में जो 99 परियोजनाएं लीं थीं, उनमें भी 7 परियोजनाएं-अर्जुन सहायक, राजघाट नहर, उत्तर प्रदेश के लहचूरा बांध, कछुरोरा बांध और मध्य प्रदेश के बेहरियापुर, एलसीवी सिंगपुर और सिंधचरण 2 के आधुनिकीकरण के काम को हमने इसमें लिया था ।

इसमें उत्तर प्रदेश की तीन परियोजनाएं हैं, राजघाट नहर, लहचूरा बांध और कचनौद बांध के निर्माण कार्य आज पूरे हो गए हैं । इसके लिए 201 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता इसमें जारी की गई है । इन परियोजनाओं के माध्यम

से बुंदेलखंड में 61 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करने के लिए नई क्षमता सृजित हुई है । पीएमकेएसवाई की जो परियोजनाएं हैं, उनसे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजनाओं में निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे ।

माननीय सभापति महोदया, केन्द्र सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए वर्ष 2009 में एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी । 7,266 करोड़ रुपये के इस पैकेज में से 3,760 करोड़ रुपये बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के हिस्सों और 3,506 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए । वर्ष 2011 में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए अलग से 100-100 करोड़ रुपये दोनों प्रदेशों को दिए गए । वर्ष 2009 में यह योजना प्रारंभ हुई, उसके बाद वर्ष 2018 तक 6,257 करोड़ रुपये बुंदेलखंड पैकेज के दोनों प्रदेशों को दे दिए गए ।

माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में केन बेतवा लिंक की चर्चा की है । मैं आपके माध्यम से नदियों से जोड़ने की परिकल्पना के बारे में भी कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं । देश वर्षों से इस बात का सपना देख रहा है । देश के सामने यह चुनौती है कि देश के लगभग एक तिहाई हिस्से में हर साल सूखा पड़ता है । देश के लगभग 13 प्रतिशत हिस्से में हर साल बाढ़ की विभीषका देखने को मिल रहा है । देश में अनेक वर्षो से, अंग्रेजों के जमाने से इस बात पर चर्चा और चिंता हो रही थी कि हम देश में इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए काम करें ।

मैं आज एक बार पुन: अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण करना चाहता हूं । जब वे देश के प्रधान मंत्री थे, देश के दूरगामी विकास के लक्ष्य को लेकर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए थे । देश हमेशा गोल्डन क्वार्डिलेटरल प्रोजेक्ट को याद रखेगा । उन्होंने देश के विकास के लिए बड़ी सड़कों के योगदान के लिए उन्होंने काम किया । उन्होंने प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कल्पना दी । उन्होंने उसी पंक्ति में देश के नदियों को जोड़ने की संकल्पना भी रखी । आदरणीय सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में एक कमेटी का निर्माण किया था । उस कमेटी ने देश भर में अध्ययन करके, कुल 30 लिंक्स

आईडेटिफाई किए, 14 हिमालयन रीजन्स में और 16 पेनिन्सुलर रीजन में थे । जिनके माध्यम से हम देश की ऐसी नदियों को, जहां सरप्लस वाटर है, उनको डेफिसिट बेसिन के साथ जोड़ सकते हैं और इन समस्याओं का स्थायी समाधान कर सकते हैं । आईडेंटिफाइड 14 लिंक्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन गई है, जो पेनिन्सुलर रीजन के हैं । जो दो लिंक्स हिमालयन रीजन के हैं, उनकी भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दी गई है । इसके अतिरिक्त उनमें से चार प्राथमिकता वाली परियोजनाएं आईडेंटिफाई की गई हैं, जिनको हम शीघ्रता से पूरा कर सकते हैं, प्राथमिकता के साथ पूरा कर सकते हैं । मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए आग्रह कि या है, वह नम्बर वन पर है । केन बेतवा लिंक परियोजना का डीपीआर तैयार हो चुका है । डीपीआर तैयार करके हम ने जिस तरह से अन्य परियोजनाओं पर काम कि या है, राज्यों ने अपने यहां इंटरस्टेट या इंट्रा-स्ट्रेट लिंक की परियोजनाएं बनाने के लिए कहा है । ऐसे कुल 47 प्रस्ताव आए हैं, हम ने उनमें से 37 इंटरस्टेट लिंक्स और इंट्रा-लिंक्स में पीएफआर को पूरा कर दिया है । यह राज्य का विषय है । जल संसाधनों का मालिकाना हक उनके पास है, हम ने उसे राज्यों के पास भेजा है कि राज्य अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति इसमें प्रदान करें । राज्य साथ में बैठ कर अपनी अंडर स्टैंडिंग डेवलप करें और उसे डेवलप करके एक मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करें, ताकि इस दिशा में काम आगे बढ़ाया जा सके । दोनों प्रदेशों ने केन बेतवा परियोजना में भी लगभग सहमति के स्तर तक पहुंचने का काम किया है । अभी कुछ विषयों में उनके बीच मतभेद था, उनके बीच छोटी-मोटी आशंका और असहमति की स्थिति थी, लेकिन आज मैं प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि हम ने दोनों राज्यों के साथ बैठ कर, उनके अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ कर विचार-विमर्श किया है ।

दोनों राज्यों के बीच में हम फाइनल सहमति के स्तर पर पहुँचे हैं, लेकिन मानसून और नॉन-मानसून समय में जल के बंटवारे को लेकर उनके बीच थोड़ा मतभेद है । लेकिन हमने अनेक बार साथ में बैठकर इसे रीसॉल्व करने के लिए काम किया है । बंटवारे के कारण एवं नॉन-मानसून सीजन में पानी की उपलब्धता को लेकर जो चिन्ता थी, उत्तर प्रदेश की उस चिन्ता को दूर करने के

लिए, जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में भी कहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में अनेक तालाब हैं, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ एवं माननीय अनुराग जी ने भी कहा था कि बुंदेलखंड ऐसा क्षेत्र है, जब पानी की कमी की बात होती है, तो लातूर की बात होती है और बुंदेलखंड की बात होती है । लेकिन बुंदेलखंड के राजाओं ने छः सौ साल से एक हजार साल पहले तक, चार सौ साल के कालखंड में दस हजार से भी ज्यादा तालाब अपने-अपने क्षेत्रों में बनवाए थे । उन तालाबों के कारण वे क्षेत्र जल-समृद्ध क्षेत्र थे । लेकिन कालांतर में वे तालाब खोते गए, गायब होते गए, उन पर अतिक्रमण होता गया, वे लुप्तप्राय हो गए । उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए 'अपना खेत, अपना तालाब' योजना के माध्यम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इनिसिएटिव लेकर काम करना प्रारंभ किया है । लेकिन उसके साथ-साथ नॉन-गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशंस ने भी इस दिशा में काम करना प्रारम्भ कि या है और इस दिशा में तेजी से काम हो रहे हैं । उन तालाबों को हम केन-बेतवा लिंक के माध्यम से भर दें, हमने ऐसे 38 तालाबों को आइडेंटिफाई किया है, ताकि उन तालाबों को हम भर दें । वे न केवल जमीन के पानी को पुनर्भरित करने का काम करेंगे, अपितु स्थाई रूप से इस क्षेत्र की जल-समस्या का समाधान करने में भी कारगर होंगे ।

महोदया, इसके कारण से दूसरी चुनौतियाँ भी हमारे सामने खड़ी होती हैं । जैसा कि मैंने कहा कि एक समस्या दूसरी समस्या को पैदा करती है । पानी की समस्या ने खेती को प्रभावित कि या और खेती ने चारे की समस्या पैदा की और चारे की कमी के कारण 'अन्ना प्रथा' की समस्या पैदा हुई ।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): नदी से नदी को जोड़ने का सपना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उसके बारे में बताइए ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: मैं वही बताने जा रहा हूँ दीदी । हम उसे बिल्कुल पूरा करेंगे । हम उसको पूरा करने की दिशा में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए काम करेंगे ।

'अन्ना प्रथा' की चुनौती हमारे सामने है । पशुधन के रूप में पहले बैल के अनेक उपयोग में आते थे, खेती में, रहट चलाने में, पानी निकालने में, कोल्हू में से तेल निकालने के काम में आते थे, लेकिन तकनीकी परिवर्तन के कारण वे अनुपयोगी हो गए । उनके अनुपयोगी होने के कारण जिस तरह की चुनौतियाँ देश के सामने आईं हैं, यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संकट है । आवारा पशुओं के संकट को दूर करने के लिए सरकार अनेक तरह से काम कर रही है । 'गोकुल मिशन' प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत देसी गौ वंश को किस तरह से समृद्ध कर सकते हैं । इसके साथ ही, सेक्स-शॉर्टेड सिमेन के माध्यम से कि स तरह से मेल काफ्स के बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, हमने इस दृष्टिकोण से काम करना प्रारंभ किया है ।

हमारे पशुधन उपयोगी बनें, हमारे पशुधन प्रोडक्टिव बनें, इस दिशा में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पशुधन विकास के लिए अलग से एक मंत्रालय क्रिएट करके एक फोकस्ड एप्रोच के साथ हमने काम करना प्रारंभ किया है ।

माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में केन-बेतवा लिंक के बारे में चर्चा की थी । मैं केन-बेतवा लिंक के परिप्रेक्ष्य में कुछ बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा । केन-बेतवा लिंक परियोजना, जो मध्य प्रदेश की केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना है, इसमें नौ लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचिंत क्षेत्र के बढ़ने की संभावना है । बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दतिया, दमोह, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय पुष्पेन्द्र सिंह जी के क्षेत्र में बांदा, महोबा और झांसी जिलों को निश्चित रूप से लाभ होगा, वहाँ के किसानों को लाभ होगा और इस पूरे क्षेत्र को पेय जल के संकट से हमेशा-हमेशा के लिए निजात मिलेगी ।

इसके लिए जो बांध बनाया जाना है, इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाना है, उसे बनाने के लिए जो एनवायरनमेंट क्लीयरेंस की जरूरत थी और जितनी तरह की स्टैच्यूटरी क्लीयरेंसेज की जरूरत थी, चाहे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो स्टैच्यूटरी क्लीयरेंस चाहिए, ...(व्यवधान)

ट्राइबल एरिया के लिए जो स्वीकृति चाहिए, वे सारी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं । हमें फर्स्ट फेज़, स्टेज-1 की इन-टोटैलिटी पर्यावरण स्वीकृति मिल गई है । केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो एक छोटा सा विषय है, जैसा मैंने जिक्र कि या, उसके बाद उन दोनों राज्यों के बीच में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर होते ही हम शीघ्र ही इस दिशा में काम करने के कगार पर आज खड़े हैं । मैं आज सदन के सामने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सपने को पूरा करने में हम लोग कामयाब होंगे और निश्चित रूप से इस दिशा में हम काम करेंगे । इस दिशा में न केवल हम पेयजल, सिंचाई क्षेत्र के लिए काम करेंगे, अपितु साथ ही साथ 46 टैंक्स जो चिन्हित किए हैं, उनमें से 38 टैंक्स को साथ में जोड़कर इस योजना के माध्यम से उस पूरे क्षेत्र को जल सुरक्षित बनाने में हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे ।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): मंत्री जी, आप उर्मिल बांध के बारे में बता दीजिए । ...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सदस्य उर्मिल बांध का विषय चर्चा में लाए हैं । अपनी चर्चा के समय भी अपना वक्तव्य देते हुए उन्होंने इस बारे में कहा था । हम उसको एग्ज़ामिन करा रहे हैं कि उसे कि स तरह इस योजना के साथ जोड़ा जा सकता है । निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के हिस्से के पानी से, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की आवश्यकता होगी, उस हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड है । हम सब लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं ।

जैसा मैंने विस्तार से आप सबके सामने विषय रखा कि हम जल संरक्षण और देश को जल समृद्ध बनाने के लिए एक हॉलिस्टिक समाधान देने की दिशा में काम कर रहे हैं । मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो यह संकल्प रखा है, क्योंकि देश की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पहले से ही इन सब विषयों पर लगातार काम कर रही है । मुझे विश्वास है, जैसा कि मैंने कहा कि हम केन-बेतवा लिंक परियोजना पर प्राथमिकता से काम कर रहे हैं । मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो यह संकल्प, रेज़ोल्यूशन इस सदन के

सामने रखा है, वे इस संकल्प को वापस लें और इस भरोसे और विश्वास के साथ में वापस लें कि हम माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में उनके संकल्प को प्रधान मंत्री जी का संकल्प बनाकर पूरा करने के लिए काम करेंगे ।

माननीय निहाल चन्द जी ने गंगानगर में पीने के पानी की, वॉटर क्वालिटी की समस्या का विषय रखा । ...(व्यवधान)

श्री निहाल चन्द : सर, सिर्फ गंगानगर ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में यही समस्या है । ...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: मैं भी वही पानी पीता हूं, मैं भी उसी दु:ख से पीड़ित हूं । वह गंगानगर के रास्ते से आने वाला पानी है । रवनीत सिंह जी भी उसी के सताए हुए हैं, हम सब लोग उसी के सताए हुए हैं । **...(व्यवधान)**

श्री निहाल चन्द : राजस्थान के मुख्य मंत्री और पंजाब के मुख्य मंत्री भी वही पानी पीते हैं । **...(व्यवधान)**

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: लुधियाना से जो अनट्रीटेड पानी, सीवेज का पानी और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, विशेष रूप से वहां की जो प्लेटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका जो अनट्रीटेड पानी सतलुज दरिया में डाला जाता है, वह पानी आगे आकर राजस्थान तक पेयजल और सिंचाई के लिए काम में आता है । पंजाब, हरियाणा और राजस्थान निश्चित रूप से उससे व्यथित हैं । हमने पंजाब की सरकार को पत्र भी लिखा, वहां आकस्मिक निरीक्षण भी करवाए हैं । हमने उनको नोटिस भी दिया है कि इन इंडस्ट्रीज़ को बंद किया जाना चाहिए । उन्होंने कमिट कि या था कि वे शीघ्र इस दिशा में ठोस कदम उठाएंगे । हमने इस संबंध में निर्देश दिया है । मंत्रालय की एक टीम जाकर उसको दोबारा इन्सपैक्ट करेगी । यह समस्या निश्चित रूप से गंभीर है । यह मेरे संज्ञान में भी है । इसके समाधान के लिए जो भी प्रयास किए जाने चाहिए, हम निश्चित रूप से वे सारे प्रयास करेंगे ।

मैं पुन: माननीय सदस्य, आदरणीय पुष्पेन्द्र सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा का इस सदन को मौका दिया । सारे माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया, मैं उन सबको भी

धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं । मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस चर्चा के लिए अनुमति प्रदान की और लगातार तीन सत्र तक, इतनी सिटिंग्स में, इतने सारे सदस्यों को मौका दिया । माननीय सभापति महोदया ने भी बिना रोके-टोके मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया । मैं आप सबका पुन: धन्यवाद ज्ञापित करते हुए माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे इस संकल्प को वापस लें । आप सब लोगों को भी, जिन्होंने इस चर्चा को गंभीरता के साथ सुना, मैं आप सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूं और अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं ।

माननीय सभापति : पुष्पेन्द्र जी, आपको मौका देने से पहले कराडी संगन्ना जी और जनार्दन मिश्र जी के कुछ प्रश्न हों तो वे पूछ लें ।

श्री कराडी संगन्ना अमरप्पा (कोप्पल): सभापति जी, जल शक्ति मंत्री से पूछना चाहता हूं कि रिवर लिंकिंग के बारे में कर्नाटक में कौन-कौन सी नदियां जुड़ी हुई है, यह बताएं?

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): सभापति महोदय, मैं जल शक्ति मंत्री जी पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जल संरचनाओं को डिस्ट्रिक्टवाइज करने का प्रयास कि या है, उसके लिए धन्यवाद । क्या वह इनको ब्लॉकवाइज करने का भी प्रयास करेंगे?

माननीय सभापति: मंत्री जी, मैं अपने आपको रोक नहीं पा रही हूं । मैं दिल्ली से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछना चाहती हूं । बिधूड़ी जी बैठें हैं, तो यह मौका बिधूड़ी जी के लिए है ।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): मैं सभापति महोदया को धन्यवाद दूंगा कि आपने दिल्ली के बारे में चिंता व्यक्त की है । यमुना नदी के पानी के लिए हमेशा झगड़ा चलता रहता है और सरकार सभी नदियों को जोड़ने का काम प्रायरिटी

पर कर रही है । आप माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अटल जी के सपने को पूरा कर रहे हैं । यमुना नदी के लिए हजारों करोड़ों रुपये का फण्ड आता है । क्या हम आने वाले 2 या 3 सालों में यह देख पाएंगे कि यमुना नदी के अंदर गोता लगाकर नहा सकें और स्वच्छ पानी का आनंद दिल्ली के लोग ले सकें और दिल्ली का जो वाटर लेवल गिर रहा है, वह ऊपर हो सके । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यमुना नदी के बारे में ऐसा विचार है?

माननीय सभापतिः मंत्री जी, इसमें थोड़ा और जोड़ लीजिए । जो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लेवल है और जो ग्राउण्ड वाटर हैवी मैटल्स की वजह से पॉल्युटेड हो चुका है और जो इंडस्ट्रीज दिल्ली से हरियाणा आदि शिफ्ट हुई हैं, क्या उसका असर दिल्ली के पानी पर हो रहा है? क्या दिल्ली सरकार ने आपसे कभी चिंता व्यक्ति की है, कभी यह विषय आपके संज्ञान में लेकर आई है या आपसे कुछ मदद मांगी है, यह भी आप बता दीजिए । आपने क्रॉप डायवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन बावजूद इसके क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ आपका कुछ तालमेल चल रहा है? एग्रीकल्चर में 89 परसेंट पानी जा रहा है तो कहीं न कहीं उस व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है । मंत्री जी, आप यह बता दीजिए और उसके बाद चंदेल जी आप अपनी बात कह दीजिए । विष्णु दयाल जी आप भी अपनी बात पूछ लीजिए ।

श्री विष्णु दयाल राम : मैडम, **256** जिलों को वाटर स्ट्रैज्ड जिलों की सूची में रखा गया है । मेरे संसदीय क्षेत्र में दो जिले पलामू और गढ़वा हैं । वे रेन साइड एरिया में पड़ते हैं । प्रत्येक वर्ष मार्च से लेकर मई के महीने तक पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं रहता है । मैंने मंत्री जी को लिखकर दिया और उन्होंने कार्रवाई भी की है, लेकि न इसके बावजूद वे दोनों जिले अभी तक सम्मिलित नहीं किए गए हैं । उन दोनों जिलों को सम्मिलित करने की नितांत आवश्यकता है, चूंकि उनके बहुत ब्लॉक्स, ब्लैक ब्लॉक्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं । वहां न केवल यह प्रॉब्लम है, बल्कि इससे जुड़ी हुई दूसरी प्रॉब्लम है । वहां आर्सेनिक और फ्लोराइड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है । मैं उसकी ओर भी मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सभापति महोदया, धन्यवाद । माननीय सदस्य ने जो कनार्टक के लिंक्स के बारे में बात की है । जो नेशनल प्रॉस्पैक्टिव प्लान है, इसमें हमने 30 लिंक्स आइडेंटिफाई करके काम करना प्रारम्भ किया है । इसमें कर्नाटक के 3 लिंक्स – अल्माटी-पैन्नार, नेत्रावती-हेमावती और बेडती-वर्धा हैं । हमने इन तीनों लिंक्स के ऊपर काम किया है ।

माननीय सभापति महोदया, इसके अतिरिक्त आपने और माननीय सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने यमुना को लेकर प्रश्न खड़ा किया है । यमुना नदी में वजीराबाद, ओखला में आने के बाद पीने का पानी शेष नहीं रहता है । सीवेज से जो पानी जाता है, वही पानी उसमें बचता है, क्योंकि उससे पहले पानी रोक लेते हैं । दिल्ली में पीने का पानी भी पर्याप्त नहीं हो पाता है । यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है । जहां तक जो अनट्रीटेड सीवेज जा रहा है, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमने जब गंगा नदी की स्वच्छता, उसकी अविरलता और निर्मलता पर काम करना प्रारम्भ कि या था । वर्षों से काम चल रहा था । वर्ष 1985 से गंगा की स्वच्छता के लिए काम हुआ, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने उसको एक नई डायनेमिक्स प्रदान की है । प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि जब हम गंगा की बात करेंगे तो पूरी गंगा बेसिन के लिए बात करेंगे । जब गंगा बेसिन के लिए काम करेंगे तो गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं, चाहे यमुना है या यमुना की सहायक नदियां कोसी या जितनी भी सहायक नदियां, हिण्डन और काली हैं, उन सबकी स्वच्छता के लिए साथ में काम करेंगे ।

पहले हमने गंगा की मूल धारा पर काम करना प्रारम्भ किया था और उसमें हमें निश्चित रूप से उल्लेखनीय सफलता मिली है । पूरे देश और दुनिया ने कुंभ और उसके बाद अनेक अवसरों पर इसे देखा है । यमुना में भी हमने उस दृष्टिकोण से काम करना प्रारम्भ किया है । देश का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो दिल्ली में है, वह कई वर्षों से अटका हुआ था । मैंने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर दिल्ली सरकार के मुख्य मंत्री जी के साथ बैठकर उस काम को प्रारम्भ किया है । वह तीन सालों में बनकर पूरा होगा । वह बनने के बाद दिल्ली का लगभग 100 प्रतिशत सीवेज ट्रीट होकर जाए, इसके लिए हमने आगे कदम बढ़ाए हैं । साथ ही साथ तब तक बायो रीमेडिएशन व अन्य टेक्नोलॉजीज़ के

माध्यम से हम इंटरवीन करके कि स तरह से नालों में हम अभी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हमने कुछ प्रयोग इस दिशा में प्रारम्भ किए हैं ।

महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा कि क्या हम कभी यमुना में गोता लगाकर नहा सकेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि बाथिंग क्वालिटी का पानी पूरी मात्रा में यमुना में रहेगा । इसके लिए निश्चित रूप से हमने योजना बनाई है । लखवार, कि शाऊ और रेनुका इन तीन जगहों पर बांध बनाकर पानी रोका जाएग । हमारे यहां केवल 60-70 दिनों के लिए 95 प्रतिशत रेन फॉल होती है । यह पानी बहकर नदी में मिलता है, इसलिए बरसात के दिनों में यमुना अपनी पूरी ऊंचाई तक बहती है । उस समय हमारे सांसदों और अन्य सभी लोगों के सामने अलग तरह की चुनौती होती है । शेष दिनों में पानी बिल्कुल नहीं रहता है । इन तीनों बांधों के बन जाने से काफी सुविधा होगी । लखवार में काम लगभग प्रारम्भ करने की स्थिति में है । माननीय न्यायालय ने उसमें कुछ टेम्परारी इंजेक्शन दिया है । मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही हम उससे बाहर आ जाएंगे । उसके बाद हम वहां काम प्रारम्भ करेंगे । वहां जब काम प्रारम्भ हो जाएगा तो कंट्रोल्ड तरीके से पानी को छोड़ने से वर्ष पर्यन्त पानी का प्रवाह बना रहेगा, जैसा कि हमने गंगा में अनुभव किया ।

माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जिस तरह अविरलता बनाए रखने के लिए एक ई-फ्लो नोटिफिकेशन जारी कि या कि कम से कम हमें एक निश्चित मात्रा में पानी लीन सीजन में और मानसून सीजन में नदी में प्रवाहित करना ही पड़ेगा । नदी एक लिविंग एंटिटी है और उसमें रहने वाले जितने भी जीव हैं, उनका नदी पर अधिकार है । इसे सुनिश्चित करने के लिए जिस तरह से गंगा के लिए नोटिफिकेशन कि या गया है, निश्चित रूप से यह बांध बनने के बाद मैं सदन के सामने जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यमुना में भी हम उसी तरह का ई-फ्लो नोटिफिकेशन करेंगे, ताकि यमुना नदी को पुनर्जीवित कर सकें । राजस्थान से जब चंबल आकर यमुना से मिलती है और उसे पुनर्जीवित करती है, उसके बीच के समय में यह एक चुनौती है । मुझे लगता है कि पॉल्यूशन का सबसे सही तरीका डायल्यूशन है । जल्दी ही हम और अधिक स्वच्छ पानी यमुना में छोड़ पाएंगे, ताकि माननीय सदस्य उसमें जब चाहे डुबकी लगाकर स्नान कर

सकेंगे । ऐसी स्थिति हम जल्द ही लाएंगे । साथ ही साथ माननीय सदस्य श्री वीडी राम जी ने जो प्रश्न कि या है कि जल शक्ति अभियान में उनके क्षेत्र के जिलों को भी जोड़ा जाए । मैंने तो अपनी चर्चा में भी कहा था कि लगभग सभी माननीय सांसदों ने मुझे पत्र लिखकर और व्यक्तिगत रूप से जल शक्ति अभियान में उनके क्षेत्र के जिलों को जोड़ने का अनुरोध कि या था ।

जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में निवेदन कि या कि 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करके उनमें काम करना प्रारम्भ कि या था, लेकि न हमने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा था कि इसी तर्ज पर अपने यहां भी इस तरह के काम को एक फोकस्ड अप्रोज लेकर वह कि स तरह से काम कर सकते हैं, इसके लिए अपने जिलों का चयन करके अपने यहां के कलेक्टर्स को नोडल अधिकारी बनाकर इस पर काम करें । मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने राज्य की सरकार से अप्रोच करें और राज्य सरकार इस दिशा में इनीशिएटिव ले । कि सी भी तरह की टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट की आवश्यकता होगी तो हम पूरी कमिटमेंट के साथ राज्य और माननीय सदस्य के साथ खड़े रहेंगे । मैं इस बात का विश्वास आपको दिलाता हूं ।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : सभापति महोदया, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि दूसरी बार क्षेत्र की जनता ने हमें चुनकर इस सदन में भेजा । हमारा हमीरपुर लोक सभा संसदीय क्षेत्र बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है । वहां पर पानी सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी कठिनाई है ।

जब मैंने यह संकल्प लगाया था तो मैं समझता हूं कि यह हमारे क्षेत्र की जनता की शुभकामनाएं हैं कि इस 17वीं लोक सभा का यह पहला संकल्प स्वीकृत हुआ । जब यह संकल्प आया तो मैं समझता हूं कि यह काम निश्चित

रूप से पूरा होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून, 2019 को यह संकल्प हमारे यहां आया था । उस दिन से संकल्प पर चर्चा हुई और देश के कोने-कोने से, सभी प्रांत के लोगों ने, सभी माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे, अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ-साथ हमारे बुंदेलखंड के लिए, हमारे यहां के छुट्टा गोवंश, जो मवेशी हैं, उनके लिए और वहां पानी का जो संकट है, उसको देखते हुए, बुंदेलखंड की जनता को उन्होंने जो समर्थन दिया है, जो हम लोगों को संबल दिया है, मैं उन सभी का आभार प्रकट करते हुए, अपनी बात प्रारम्भ करता हूं ।

महोदया, हमारे इस महत्वपूर्ण संकल्प पर माननीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी ने बात रखते समय यह विश्वास व्यक्त किया कि इस संकल्प को माननीय प्रधान मंत्री जी का संकल्प बनाकर के हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे । ऐसे इस महत्वपूर्ण संकल्प पर आदरणीय निशिकांत दुबे जी, श्री निहाल चंद जी, श्री मुकेश राजपूत जी और हमारे बुंदेलखंड के वरिष्ठ सांसद श्री भानु प्रताप वर्मा जी ने अपनी बात रखी । श्री भानु प्रताप वर्मा जी ने एक बात बोली थी कि आज पूरे 9 माह हो गये हैं, जब से इस संकल्प पर चर्चा आरम्भ हुहै । वह कह रहे थे कि यह योग दिवस के दिन प्रारम्भ हुआ था तो यह पूरा होगा और हम लोगों को इसका लाभ मिलेगा । माननीय मंत्री जी के उद्बोधन से हमें यह लगा भी है कि इस पर हम लोगों को सफलता मिलेगी । विपक्ष के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी, भले ही वह पश्चिम बंगाल से आते हैं, लेकिन उन्होंने बुंदेलखंड का समर्थन किया है । वह इस समय सदन में नहीं हैं, लेकिन मैं उनका आभार प्रकट करता हूं । आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल जी, हमारे बांदा से सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी, श्री नायाब सिंह सैनी, हमारे झांसी से सांसद श्री अनुराग सिंह शर्मा जी, राजस्थान से श्री दुष्यंत सिंह जी, श्री पी.पी. चौधरी जी, श्री भगीरथ चौधरी जी, श्री गुमान सिंह जी, श्री जनार्दन मिश्र जी, श्री रितेश पाण्डेय जी, श्री हनुमान बेनीवाल जी और अंत में हमारे जम्मू-कश्मीर से सीनियर मैम्बर श्री हसनैन मसूदी जी ने भी इस संकल्प पर अपनी बात रखी है ।

महोदया, मैं सभी का आभारी हूं क्योंकि जल की आवश्यकता सभी को है, चाहे सुदूर कोई ग्रामीण क्षेत्र हो या दिल्ली की बात हो । अभी जब बात हो रही थी तो मैं देख रहा था । सभापति महोदया, आप भी आसन पर विराजमान हैं, आपके मन में भी अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जिम्मेवारी का एहसास था, लेकिन मर्यादा में उसको नहीं उठाना चाहती थीं । आपने बिधूड़ी जी को मौका दिया और उसके बाद भी आपको लगा कि कुछ बचा है तो आपने उसको सदन में रखा ।

महोदया, मेरा यह मानना है कि देश के कोने-कोने से लोगों ने इस पानी की समस्या को लेकर जो बात रखी है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को यह लगता होगा कि हमारा संसदीय क्षेत्र ज्यादा संकट में है । लेकिन सभापति महोदया, मैं आपको बहुत भावुकता के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से जितना पलायन हुआ है और जितना पलायन मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर, महोबा, राठ, चरखारी, छिंदवारी से हुआ है, शायद किसी अन्य लोक सभा क्षेत्र से इतना पलायन नहीं हुआ होगा । मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि हमारे यहां अगर जल का संकट नहीं होता तो हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती ।

महोदया, संकट कैसे बढ़ता चला जाता है? आज मंत्री जी ने जब अपनी बात रखी कि एक हजार साल पहले वहां के राजाओं ने तालाब बनवाए थे । यह एक हजार साल पहले की बात है । सौभाग्य से मेरे पूर्वजों के बनवाए हुए तालाब वहां हैं । वे छोटे तालाब नहीं हैं, एक-एक हजार हेक्टेयर और पांच-पांच सौ हेक्टेयर के तालाब हैं । वहां के किसी भी तालाब को तालाब या पोखर नहीं कहा जाता है । हमारे क्षेत्र में तालाबों के नाम होते हैं, जैसे तीरथ सागर, मदन सागर, कल्याण सागर और रहलिया सागर । हमारे यहां तालाबों का स्वरूप बहुत बड़ा है और इसलिए सभी को सागर के रूप में बोला जाता है । एक हजार वर्ष पूर्व जब चंदेल शासन काल में उनका निर्माण हुआ था, तब वहां के जल प्रबंधन में देश की आजादी के बाद से कमी आयी और वह बढ़ नहीं पाया । जब से आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने हैं, उनके आने के बाद से पूरे देश की उम्मीदें जगी हैं । हमारे बुंदेलखंड के भी एक-एक गांव में लोगों को यह उम्मीद जगी है

कि आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश और क्षेत्र की समस्याओं का निदान होगा। जैसा कि अभी बात आयी, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकि न मुझे यह तो पता था कि वर्ष 2021 तक योगी आदित्यनाथ जी ने घर-घर में "नल से जल" पहुंचाने का निर्णय किया है।

मैं समझ रहा था कि वह काम सिर्फ मेरे बुंदेलखंड में ही पूरा हो रहा है, लेकि न वह काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। उन्होंने प्रदेश में भी जो जल शक्ति मंत्रालय बनाने का काम कि या है, तो मेरे क्षेत्र की जनता माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है, जिसका आश्वासन माननीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी ने दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ये जो काम हैं, ये काम निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में पूरे होंगे।

महोदया, मेरी बात को रखते समय जो भी बातें आई हैं, हमारा जो बिल है कि नदियों को लिंक करके बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की व्यवस्था के लिए, जो उसका मुख्य कारण है कि इस बिल में केन-बेतवा रिवर लिंकिंग और छुट्टा गोवंश की बात जोड़ी गई है, वह इसलिए जोड़ी गई है कि अगर हम लोगो ं को खाद्यान्न का संकट होता है, तो हम लोग वह कहीं से भी मंगा लेते हैं। देश का कोई भी साधन संपन्न व्यक्ति जम्मू-कश्मीर से सेब भी प्राप्त कर लेता है और वह दुनिया के कि सी भी देश से ड्राई फ्रूट्स भी मंगा लेता है, लेकि न उस क्षेत्र की जो गरीब जनता है, वह वहां से अपने खाद्यान्न के लिए अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती है। अगर वह कि सी भी प्रकार से ले भी आता है, तो मैं इस बात को बड़े दर्द के साथ, बड़ी भावुकता के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ रखना चाहता हूं।

महोदया, गाय पालने वाले लोग अमीर लोग नहीं होते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन कि सान हैं, वे लोग गाय पालते हैं। मैं हमेशा यह कहा करता हूं कि किसान में वह ताकत है, चाहे उसके पास भूमि भी न हो, तो भी वह किसानी करता है। दूध का उत्पादन करना कि सी कि सानी से कम नहीं है। वह वही

किसान करता है, जो भूमिहीन हो गया है, कर्ज में डूबकर उसकी जमीन बिक गई है । कुछ लोग पलायन कर गए हैं और जो लोग पलायन नहीं कर पाए हैं, उनको जो दिक्कत महसूस हुई, तो उन लोगों ने यह सोचा कि हम गोवंश का पालन करें, उससे दूध का उत्पादन करें, ताकि अपना भरण-पोषण कर सकें ।

महोदया, जब मेरे क्षेत्र के लोगों ने दुग्ध उत्पादन के लिए काम कि या, तो मेरे क्षेत्र में चारे का संकट पैदा हो गया ।...(व्यवधान) सभापति महोदया, मुझे कम से कम 10 मिनट का समय देने का कष्ट करें । यह बहुत गंभीर विषय है । महोदया, मैं आपसे यह चाहता हूं कि मुझे कम से कम दस मिनट का समय जरूर दिया जाए ।

सभापति महोदया, जब वह गोवंश था, जब लोग गोवंश के लिए मजबूर हुए और उनको चारा नहीं मिला, वे खाने के लिए गेहूं-चावल कहीं से ले आते हैं । लेकि न देश के किसी भी कोने से भूसा लाने के लिए, वे पंजाब से भूसा नहीं ले जा सकते हैं । जब भूसा इतना महंगा मिलेगा, तो वे कैसे उसको ले पाएंगे । उसी का कारण है कि हमारे बुंदेलखंड के किसानों को अपना गोवंश छोड़ना पड़ा है और उससे जितनी भी प्रकार की कठिनाइयां पैदा हुई हैं, जब गोवंश छूटा, तो उसने उन्हीं किसानों के खेतों को चरना शुरू कर दिया । आज यह स्थिति है कि वहां का किसान दिन भर खेतों में मेहनत करता है और रात भर अपने खेतों में गाय से, गोवंश से अपने खेत की चौकीदारी का काम करता है । सरकार इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है । सरकार के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं, वे सराहनीय हैं ।

सभापति महोदया, मैंने इसी सदन में यह मांग की थी, जब मैं यहां पर पिछली बार 16वीं लोक सभा में था, तब मैंने यह मांग की थी कि हमारे बुंदेलखंड में जो गोवंश पालने वाले लोग हैं, उन कि सानों को 1,000 रुपये प्रति माह सरकार देने का काम करे । तब मुझे हमारे साथियों ने यह बोला था कि आप सत्ता दल के सांसद हैं, आप विपक्ष के सांसदों की मांग कैसे रख रहे हैं । मैंने यह कहा था कि यह विपक्ष के सांसद की मांग नहीं है, हमारी पार्टी हमको यह अधिकार देती है कि अपने क्षेत्र की भलाई के लिए आप अपनी कोई भी बात

बड़ी दृढ़ता के साथ रख सकते हैं । मैंने इसकी मांग की थी । मैं इस बात के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करता चाहता हूं । मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं । पूरे देश में हमारा उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश बना है, जहां के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पर प्रति गाय 900 रुपये के हिसाब से देना प्रारंभ कि या है ।

सभापति महोदया, मैं यह समझता हूं कि हमारे इस सदन में बोली हुई कोई भी बात व्यर्थ नहीं जाती है । हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं । हम लोग यह मानते हैं कि हृदय की इच्छा अवश्य पूर्ण होती है, यदि मिथ्या न हो । हम लोग इस बात को इस सदन में दिल से उठाते हैं । हमने जिन बातों को दिल से उठाया है, तो हमारे क्षेत्र में उन सब चीजों का समाधान निकला है और हम लोगों को बहुत-सी योजनाएं मिली हैं । अभी गोवंश की जो बात हुई है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि अभी समय की मर्यादा है । मैं यहां पर बहुत-सी बातें इसलिए रखना चाहता था कि वह सदन के संज्ञान में आएगी । लेकि न मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में जो गोवंश की समस्या है, उसके लिए खाद्यान्न के जो संकट हैं, जो केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, वह नितांत आवश्यक है । यहां पर माननीय मंत्री जी ने उसके ऊपर बड़े ही विस्तार से जवाब दिया है । मैं एक और बात कहकर अपनी बात को पूरी करूंगा कि हमारे यहां लगभग 40 वाटर बॉडीज़ हैं, माननीय मंत्री जी आप उनको केन-बेतवा रिवर लिंक से जोड़ने का काम कर रहे हैं । मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने उसको बहुत ही संजीदगी से लिया है । उस संदर्भ में आपने कई बार मंत्रालय में अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग भी कराई है और मेरी उनसे बात भी हुई है । आप उसके लिए स्वयं संजीदा हैं ।

आपने उसको बहुत संजीदगी से लिया और आपने उस संबंध में अपने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग कराई, बात हुई और आप उसके लिए स्वयं संजीदा हैं । 25 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मेरे क्षेत्र से, सूखे क्षेत्र से निकल कर जाए और उसके बाद हमारे मजगुआं, बेलाताल, उर्मिल बांध और जितने भी ये सैकड़ों की संख्या में तालाब हैं, अगर वे वंचित रह जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इस योजना के साथ न्याय भी नहीं होगा और मेरे क्षेत्र के साथ भी

न्याय नहीं होगा । क्योंकि उर्मिल बांध को अगर आप पानी देंगे, इतना अच्छा सर्वे हमारे इंजीनियरों ने कि या है कि उस एक बांध में पानी आने से कम से 40 तालाबों में नहर के द्वारा पानी पहुंचता है । अगर उर्मिल बांध में पानी नहीं पहुंचेगा तो 40 वॉटर बॉडीज़ वंचित रह जाएंगी और हमारे क्षेत्र के जो पूर्वजों के बनवाए हुए, बड़े-बड़े सरोवर हैं, वे छूट जाएंगे । वही एकमात्र उसका निदान है कि हमारे पूरे क्षेत्र में एक लाख 60 हजार हेक्टर भूमि सिंचित होनी है ।

सभापति महोदय, मैं अंत में आपका आभार प्रकट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आपने, माननीय मंत्री जी ने, भारत सरकार ने, सदन के सभी सदस्यों ने, सभी लोगों ने, देश के कोने-कोने से पधारे हुए सभी माननीय सदस्यों ने, हमारे पिछड़े क्षेत्र के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, हम लोगों का समर्थन कि या, इस विभाग का समर्थन कि या । माननीय मंत्री जी ने बोला है कि इस संकल्प को आप वापस लें, सरकार इसके लिए स्वयं चिंतित है । उन्होंने जो बात बोली है, आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि इस संकल्प को माननीय प्रधान मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प बना कर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे । इस बात को मानते हुए और माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को मानते हुए, मैं इस संकल्प को इस उम्मीद के साथ वापस लेता हूँ कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जितनी भी जल प्रबंधन की चीजें हैं, उनको जल्दी से जल्दी शीघ्रता में वरियता क्रम में पूरा कि या जाएगा । मैं अपना संकल्प वापस ले कर पुन: एक बार सभी का आभार प्रकट करता हूँ ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए सहमत हो जाती है कि अंतत: उनके हिस्से का जो जल है, अपने हिस्से के जल में से यदि वे उर्मिल बांध में पुनर्भरण के लिए राजी होते हैं तो हम निश्चित रूप से इसको छोड़ कर, उसको भरवाने के लिए इस योजना के साथ जोड़ने के लिए काम करेंगे ।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, भारत सरकार के आश्वासन के बाद मैं इस संकल्प को वापस लेता हूँ ।

HON. CHAIRPERSON : Has the hon. Member leave of the House to withdraw his Resolution?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

HON. CHAIRPERSON: Now, Item No. 18.

Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik Nimbalkar – not present.